राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 335, पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, रविवार , 13 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

बारबरा को फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब

पेरिस, (एजेंसी)। चेक गणराज्य की गैर वरीय बारबोरा क्रेजीकोवा ने अनास्तासिया पेवलियुचेंकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से हराकर फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया। क्रेजीकोवा के कैरियर का यह पांचवां खिताब है। 40 साल के बाद किसी चेक महिला ने यह खिताब जीता है। वहीं सर्बिया के नोवाक जोकोविच का फ्रेंच ओपन में रविवार को फाइनल में ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास से सामना होगा। (खेल पेज भी देखें)

भारतीय मूल की पत्रकार मेघा को पुलित्जर अवार्ड

न्यूयॉर्क, (एजेंसी)। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने अशांत शिंजियांग प्रांत में लाखों मुसलमानों को हिरासत में रखने के लक्ष्य से चीन द्वारा गोपनीय तरीके से बनाए गए जेल और अन्य भवनों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की थी। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में शिंजियांग प्रांत की सीरीज के लिए राजगोपालन को इस पुरस्कार से नवाजा गया है।

नए आईटी नियमों से कोई छूट नहीं: केंद्र

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों को तत्काल प्रभाव से आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों का पालन करना होगा। केंद्र ने उन्हें नए डिजिटल मीडिया नियमों के दायरे से छूट देने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने मुख्यधारा यानी मेनस्ट्रीम मीडिया को नई आईटी नियमों में कोई छूट प्रदान नहीं करने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि संगठनों की वेबसाइटों को कानून के दायरे में लाने का औचित्य सुविचारित है। मंत्रालय का कहना है कि कानून में किसी तरह के अपवाद को शामिल करना उचित नहीं है।

सोपोर में आतंकी हमले में दो जवान शहीद

बारामूला, (एजेंसी)। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में शनिवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस पर आतंकी हमले में दो कांस्टेबल और तीन नागरिक मारे गए और एक अधिकारी सहित दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह हमला लश्कर- के आतंकियों ने सोपोर के मुख्य चौक पर एक नाका पार्टी पर दिनदिहाड़े किया। हमले में शामिल लश्कर आतंकियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें मार गिराया जाएगा। मुकेश कुमार के नेतृत्व में सोपोर पुलिस थाने की एक टीम ने शनिवार को जिले के सोपोर में कोविड-19 प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए एक नाका स्थापित किया था।

इस साल 60 हजार को हज यात्रा की अनुमति

रियाद, (एजेंसी)। सऊदी अरब ने कहा है कि कोरोना के चलते इस साल 60 हजार से अधिक लोगों को हज की अनुमति नहीं होगी और वे सभी स्थानीय होंगे। सरकार द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी पर हज एवं उमरा मंत्रालय का हवाला देते हुए एक बयान में यह घोषणा की गई है। इस साल हज जुलाई के मध्य में शुरू होगा। इसमें 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग हिस्सा ले सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि हज यात्रियों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य है। सऊदी अरब ने हाजियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा और उनके देशों की सुरक्षा के बारे में निरंतर विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है।

जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला

ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री

कोविड वैक्सीन पर 5 फीसदी टैक्स जारी रहेगा

नई दिल्ली ■ एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 44वीं बैठक शनिवार को हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है।

इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी।

वैक्सीन पर जीएसटी का आम जनता पर असर नहीं

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में यह 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में वैक्सीन पर जीएसटी का आम जनता पर कोई असर नहीं होगा। उधर, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन फ्री में देने का प्रावधान किया है। दवाइयों पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक कर दिया गया। कोविड से लड़ाई में रिलीफ मैटेरियल पर भी जीएसटी 5 फीसदी किया गया है।

जीएसटी की नई दरें

एंबुलेंस पर पूर्व में 28 फीसदी जीएसटी लगता है जिस पर 12 फीसदी किया गया है। कोविड वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, जिसे घटाया नहीं गया। टोसिलिजुमैब एव एम्पुोथ्रेसिन-बी पर जीएसटी 5 फीसदी से घटाकर शून्य किया गया है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कंसट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआई-पीएपी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, इलेक्ट्रिक फर्नेसेज, हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस, हेपारीन दवा, कोविड टेस्ट किट पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। आरटी-पीसीआर मशीन पर टैक्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है, जिसे कम नहीं किया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग किट्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है जिसे कम नहीं किया गया है। कोविड टेस्टिंग किट निर्माण के लिए कच्चे माल पर जीएसटी में कटौती नहीं की गई है। हैंड सेनेटाइजर, थर्मामीटर और दाह संस्कार के लिए उपयोगी उपकरण और उसकी स्थापना आदि पर जीएसटी 5 प्रतिशत किया गया है।

आज जारी होगी अधिसूचना

वित्त मंत्री ने कहा कि जिन सामग्री पर छूट दी गई है, उस पर छूट कि अधिसूचना रविवार को जारी की जाएगी। जीएसटी की यह दर 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगी। उसी दिन जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक होगी।

एंबुलेंस पर अब 12 फीसदी जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया है। अभी तक एंबुलेंस पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जा रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज में टोसिलिजुमाब और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। इन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। काउंसिल ने इन दवाओं पर जीएसटी नहीं लेने का फैसला किया है।

मंत्री समूह की सिफारिशें मंजूर

जीएसटी काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए आठ मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए दरों में कटौती का फैसला किया गया है।

आरटी-पीसीआर मशीन पर टैक्स में कोई कटौती नहीं

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी कई अन्य वस्तुओं पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। आरटी-पीसीआर मशीन, आरएनए मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इन पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग किट्स पर लगने वाले 12 फीसदी टैक्स को भी बरकरार रखा गया है। कोविड टेस्टिंग किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 समिट को वीसी से किया संबोधित

'वन अर्थ, वन हेल्थ' का दिया मंत्र

डब्ल्यूटीओ में वैक्सीन पेटेंट में छूट के लिए जी 7 का मांगा समर्थन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। जी-7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लेते हुए अपने संबोधन में 'वन अर्थ, वन हेल्थ' का मंत्र दिया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने विशेष रूप से पीएम के इस मंत्र का उल्लेख किया और इसका मजबूत समर्थन दिया। इस समिट में पीएम मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर डिजिटल माध्यम से इस सम्मेलन में शिरकत की हैं। इस समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ट्रिप्स छूट को लेकर पीएम मोदी के साथ हुई अपनी चर्चाओं का भी उल्लेख किया। समिट के दौरान फ्रेंच राष्ट्रपति ने भारत जैसे वैक्सीन उत्पादकों को कच्चे माल की आपूर्ति का आह्वान किया ताकि पूरी दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

पीएम ने अपने संबोधन में वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए वैश्विक सामूहिक प्रयास का समर्थन भी किया। प्रधानमंत्री ने डब्ल्यूटीओ में वैक्सीन पेटेंट में छूट के लिए जी -7 का समर्थन मांगा।

सत्र के दौरान, पीएम मोदी ने भारत में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जी-7 और अन्य गेस्ट देशों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। पीएम ने संपर्क ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग के बारे में भी बताया और अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया। वहीं वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई।

बिहार में सियासी अटकलों को मिली नई हवा, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर जदयू ने एनडीए के सामने रखी शर्त

पटना । बिहार का सियासी पारा चरम पर है। राजद, भाजपा, हम और वीआइपी की ओर से आ रहे बयानों के बीच जदयू ने शनिवार को नई हवा दे दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड (जदयू) अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान चाहता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इसको लेकर बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए आरसीपी ने एनडीए के साथियों को सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल में स्थान मांगा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए का हिस्सा जदयू भी है। ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू को भी तरजीह मिलनी चाहिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि गठबंधन के साथियों को सम्मान मिलना चाहिए। आरसीपी के बयान से देश से लेकर बिहार की राजनीति को नई हवा मिल गई है। जदयू किसे केंद्र में भेजना चाहता है यह तो साफ नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है।

एनडीए में हैं जदयू के 16 सांसद

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बदलाव संभव है। ऐसे में बिहार से जदयू ने भी अपनी हिस्सेदारी जाहिर कर दी है। अभी एनडीए गठबंधन में जदयू के 16 सांसद हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार के समय जदयू के शामिल होने की चर्चा थी मगर अंत में बात नहीं बनी। कहा जाता है कि उस समय आरसीपी सिंह के मंत्री बनने की बात थी, मगर ऐसा नहीं हुआ।

बीजेपी और मांझी की पार्टी कर रही कटाक्ष-गौरतलब है कि बिहार एनडीए में भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के साथी बीजेपी और हम इशारों-इशारों में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। शुक्रवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी की राजद विधायक तेजप्रताप यादव से मुलाकात हुई थी।

भाजपा का दावा- क्लब हाउस चैट में दिग्विजय बोले, आर्टिकल 370 करेंगे बहाल

आडियो चैट में पत्रकारों से बोले दिग्विजय सिंह

नई दिल्ली । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कश्मीर में धारा 370 बहाल करने पर विचार करने का बयान देकर राजनीतिक हल्कों में हलचल पैदा कर दी है।

क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल से जवाब में ही दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में दिग्विजय सिंह कहते हैं, यहां (जम्मू-कश्मीर) से जब धारा 370 हटाई गई, तब लोकतंत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और न ही इसमें कश्मीरियत का ख्याल रखा गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और आर्टिकल 370 बहाल करेंगे।

वहीं दूसरी और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस ऑडियो चैट को ट्वीट करते हुए ट्विटर पर लिखा है दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 बहाल करने पर पुनर्विचार की बात कही। उन्होंने हिन्दू कट्टरपंथी का जिक्र किया। कांग्रेस राष्ट्रविरोधियों का क्लब हाउस है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी वायरल चैट को ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी।

डीसीजीआई ने दी कोलचीसीन के क्लीनिकल परीक्षण को मंजूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने सीएसआईआर और लक्साई लाइफ साइंसेज को कोविड-19 मरीजों पर कोलचीसीन दवा के क्लीनिकल परीक्षण की मंजूरी दे दी है। सीएसआईआर के महानिदेशक के सलाहकार राम विश्वकर्मा ने बताया कि सामान्य देखभाल/इलाज के साथ कोलचीसीन का उपयोग ह्रदय रोग से पीड़ित कोविड-19 मरीजों के लिए मददगार साबित होगा और यह प्रो-इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स को कम करके जल्दी संक्रमण मुक्त होने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हुए कई अध्ययनों से इसकी पुष्टि हुई है कि ह्रदय रोग से पीड़ित कोविड-19 मरीजों को जान को खतरा है। इससे काफी लोगों की मौत हो रही है। इसलिए नई दवा की जरुरत है। सीएसआईआर और लक्साई लाइफ साइंसेज हैदराबाद को डीसीजीआई ने कोविड-19 मरीजों के इलाज में कोलचीसीन दवा के उपयोग के प्रभाव और सुरक्षा के संबंध में दूसरे चरण का क्लीनिकल परीक्षण करने की मंजूरी दे दी है।

सोपोर में पुलिस-सीआरपीएफ की टीम पर लश्कर-ए-तैयबा का हमला, दो पुलिसकर्मी शहीद और तीन नागरिकों की मौत

जम्मू । जम्मू-कश्मीर के सोपोर इलाके में एक और आतंकी हमले की घटना सामने आई है. जिले के आरामपोरा में नाका पर आतंकवादियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम को निशाना बनाकर उन पर फायरिंग की. जानकारी के मुताबिक, उत्तरी कश्मीर के सोपोर के आरामपोरा इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की. इस इस हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और तीन स्थानीय नागरिकों की भी मौत हो गई, वहीं दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं. कश्मीर के ढ्ढत्र विजय कुमार ने कहा, सोपोर में इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है.

एक अधिकारी ने बताया कि इस बीच भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों की एक टीम पर हमला कर दिया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी कश्मीर जिले के जैनपोरा इलाके के अगलर में आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल पर हमला कर दिया. अधिकारी ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

एक इस्लामी जिहादी समूह है लश्कर-लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में स्थित एक इस्लामी जिहादी समूह है. यह संगठन समूचे दक्षिण एशिया को कट्टरपंथी बनाने में यकीन रखता है. इसकी स्थापना 1987 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादियों में से एक हाफिज सईद ने की थी. लश्कर पर भारत में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है, खासकर साल 2001 के भारतीय संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों के. इसे भारत, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर सर एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है. दिसंबर 2001 में अमेरिका ने इन संगठन को अपनी आतंकी लिस्ट में शामिल कर दिया था. वहीं, भारत ने भी इसे एक कानून के तहत बैन कर दिया था.

मार्च में भी सोपोर में किया गया था आतंकी हमला- अधिकारी ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है. आतंकी संगठन लगातार सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे पहले, मार्च के आखिर में भी सोपोर में ही आतंकी हमले की घटना सामने आ चुकी है. 29 मार्च को सोपोर में बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था. इस हमले में एक पुलिस अधिकारी और एक स्थानीय नागरिक को भी गंभीर चोटें आई थी, तो वहीं एक पुलिस अधिकारी ने अपनी जान गंवा दी थी. पिछले महीने इस क्षेत्र के नाथीपोरा इलाके में सुरक्षाबलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ जारी रही.

हैदराबाद के सिकंदराबाद में भारतीय सेना की तकनीकी प्रवेश योजना पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड में भाग लेते कैडेट।

गठबंधन अकाली दल और बीएसपी में सीटों पर सहमति बनी, 97+20=117

पंजाब में अकाली दल, बीएसपी साथ-साथ

चंडीगढ़ ■ एजेंसी

एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को संयुक्त प्रेस सम्मेलन में मिठाई खिलाई।

पंजाब में आगामी विधानसभा को चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। राज्य में होने वाले कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव में 20 सीटों पर बीएसपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी जबकि बाकी के बचे 97 सीटों पर अकाली दल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे। गठबंधन के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यह गठबंधन राज्य के में जनता के बहु-प्रतीक्षित विकास के नए युग की शुरूआत करेगा। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब में शनिवार से शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित गठबंधन यह एक नया राजनीतिक व सामाजिक पहल है, जो निश्चय ही यहां राज्य में जनता के बहु-प्रतीक्षित विकास, प्रगति व खुशहाली के नए युग की शुरूआत करेगा।

कांग्रेस पर बोला हमला

बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि वैसे तो पंजाब में समाज का हर तबक़ा कांग्रेस पार्टी के शासन में यहां व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी आदि से जूझ रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, किसानों, युवाओं व महिलाओं आदि पर पड़ रही है, जिससे मुक्ति पाने के लिए अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब की समस्त जनता से पुरज़ोर अपील है कि वे अकाली दल व बीएसपी के बीच शनिवार को हुए इस ऐतिहासिक गठबंधन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए यहां साल 2022 की शुरुआत में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में पूरे जी-जान से अभी से ही जुट जाएं।

प्रकाश सिंह बादल ने मायावती से की बात- गठबंधन के बाद अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से फोन पर बात की और गंठबंधन के लिए बधाई दी। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हम लोग जल्द ही आपको पंजाब आने के लिए निमंत्रण देंगे।

संक्षिप्त समाचार

तिब्बत की भाषा और संस्कृति मिटाने के लिए हर हथकंडा अपना रहा चीन, तिब्बती स्कूलों को कर रहा बंद

बीजिंग एजेंसी। तिब्बत पर अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत करने के लिए चीन हर वो चाल चल रहा है, जो नैतिकता के अनुरूप बेहद गलत है. इसी क्रम में वह तिब्बत की संस्कृति को कुचल रहा है. वह वहां की भाषा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है. ऐसी खबरें हैं कि चीन तिब्बत के उन स्कूलों में ताला लगा रहा है, जहां शिक्षा का माध्यम तिब्बती भाषा है . चीन के सिचुआन प्रांत में इन तिब्बती स्कूलों को बंद किया जा रहा है और छात्रों को सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. जहां चीनी भाषा यानी मंदारिन में पढ़ाई कराई जाती है. चीन ने स्कूलों को बंद करने की कायराना हरकत 2020 के आखिर में ही शुरू कर दी थी. वह लोगों पर जबरन अपनी संस्कृति और भाषा थोप रहा है . रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले सिचुआन प्रांत के दजाचुका क्षेत्र में कई तिब्बती निजी स्कूल थे, जहां तिब्बती संस्कृति में पढ़ाया जाता था. लेकिन अब इन्हें बंद किया जा रहा है और इसके पीछे का कोई वाजिब कारण भी नहीं बताया जा रहा. सूत्रों ने बताया, प्रशासन का कहना है वह ऐसा इन किताबों और शिक्षण सामग्री के इस्तेमाल में समानता लाने के लिए कर रहा है.

मंदारिन भाषा वाले होर्डिंग्स- इसके अलावा चीन ने शॉपिंग मॉल से लेकर बस स्टेशन तक, हर जगह मंदारिन भाषा लिखे होर्डिंग लगाए हुए हैं. जिनपर अंग्रेजी के साथ मंदारिन लिखी दिखाई देती है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2035 के शिक्षा प्लान के मुताबिक देशभर में शिक्षा के हर स्तर में चीनी विशेषताओं को जोड़ना उद्देश्य रखा गया है. इससे पहले चीन ने अपनी इन्हीं नीतियों को कब्जे वाले मंगोलिया में भी थोपा था. जिसके खिलाफ वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस स्थान को इनर मंगोलिया भी कहते हैं.

शिंजियांग में भी बरपा रहा कहर- चीन इस क्षेत्र की मूल भाषा को भी खत्म कर रहा यहां मंदारिन को प्राथमिक भाषा के तौर पर लागू कर रहा है. जिससे स्कूलों में मंदारिन में ही पढ़ाई कराई जाए . यहां मंदारिन को अनिवार्य करते हुए मंगोलियाई भाषा को दूसरा दर्जा दिया गया. चीन की ये बर्बरता मंगोलिया और तिब्बत के अलावा शिंजियांग में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. वह अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक और शैक्षिक तौर पर भेदभाव कर रहा है. यहां के अल्पसंख्यक और जातीय समूहों द्वारा करीब 80 भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन चीन सभी लोगों पर मंदारिन बोलने का दबाव बना रहा है. चीन ने अपनी इस नीति की शुरुआत 1950 के दशक से ही कर दी थी.

अंटार्कटिक ग्लेशियर पर बढ़ रहा संकट, पिघलने से बचाने वाली बर्फ की परत तेजी से हो रही गायब

वाशिंगटन, एजेंसी । पहले से ही नाजुक स्थिति वाला अंटार्कटिक का ग्लेशियर और अधिक असुरक्षित प्रतीत होने लगा है. ऐसा इसलिए क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से ली गई तस्वीरों में बर्फ की वह परत पहले के मुकाबले तेजी से टूटती हुई नजर आ रही है, जो इस ग्लेशियर को पिघलाकर समुद्र में मिलने से रोकती है. एक नए अध्ययन में बताया गया है कि यह परत टूटने हुए विशाल हिमखंडों को जन्म दे रही है. 'पाइन आईलैंड' ग्लेशियर की बर्फ की परत का टूटना 2017 में तेज हो गया था. इससे वैज्ञानिकों को चिंता सताने लगी थी कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का पिघलना अनुमानित कई सदियों के मुकाबले बहुत जल्दी होगा. तैरती बर्फ की यह परत तेजी से पिघलते ग्लेशियर के लिए बोतल में एक कॉर्क के समान है और ग्लेशियर के बर्फ के बड़े हिस्से को महासागर में बह जाने से रोकती है . अध्ययन के मुताबिक बर्फ की यह परत 2017 से 2020 के बीच ग्लेशियर से 20 किलोमीटर पीछे तक हट गई है. ढहती हुई परत की तस्वीरें यूरोपीय सैटेलाइट से 'टाइम-लैप्स' वीडियो में ली गई, जो हर छह दिन में तस्वीरें लेता है. टाइम लैप्स फोटोग्राफी तकनीक से लिए गए वीडियो को सामान्य गति पर चलाने से, समय तेजी से बीतता दिखता है. अध्ययन के प्रमुख लेखक, 'यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन' के ग्लेशियर विशेषज्ञ इयान जॉगिन ने कहा, 'आप देख सकते हैं कि चीजें कितनी तेजी से टूट रही हैं . इसलिए यह बिलकुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ का तेजी से टूटना अपने आप में ग्लेशियर को कमजोर कर रहा है.'

बर्फ टूटने की तीन घटनाएं हुई- उन्होंने कहा कि अब तक हमने मुख्य परत का संभवतः 20 प्रतिशत हिस्सा गंवा दिया है. जॉगिन ने बताया कि 2017 से 2020 के बीच बर्फ टूटने की तीन बड़ी घटनाएं हुईं जिसमें आठ किलोमीटर लंबे और 36 किलोमीटर तक चौड़े हिमखंड उत्पन्न हो गए थे. जो बाद में बहुत से छोटे-छोटे हिस्सों में बंट गए. बर्फ टूटने की छोटी-छोटी घटनाएं भी हुईं. यह अध्ययन 'साइंस एडवांसेस' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. इससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन कितना घातक होता जा रहा है.

अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा- दो में एक भारतीय-अमेरिकी नस्लीय भेदभाव का शिकार

वाशिंगटन, एजेंसी। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले हर दो में से एक भारतीय-अमेरिकी भेदभाव से पीड़ित है। यानी अमेरिका में भी भारतीय-अमेरिकी समुदाय को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बता दें कि भारतीय अमेरिकियों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी के एक फीसद से कुछ अधिक है। अमेरिका में सभी पंजीकृत मतदाताओं में एक फीसद से भी कम है। हालांकि, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अमेरिका सर्वाधिक पसंदीदा जगह है। अमेरिका में करीब 40 लाख की बड़ी संख्या अमेरिका में रहती है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय-अमेरिकी जो कि अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े अप्रवासी समूह के रूप में हैं, नियमित रूप से भेदभाव का सामना करते हैं। यह सर्वेक्षण के मुताबिक हर दो में से एक भारतीय-अमेरिकी भेदभाव से पीड़ित है। इसके मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान पिछले साल हर दो में से एक भारतीय अमेरिकी को भेदभाव झेलना पड़ा और नस्लीय आधार पर सबसे ज्यादा पक्षपात देखा गया । यह रिपोर्ट भारतीय अमेरिकियों की सामाजिक वास्तविकता-2020 भारतीय अमेरिकी दृष्टिकोण सर्वेक्षण पर आधारित है। यह सर्वेक्षण जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और कार्नेगी एंडोमेंट ने एक पोलिंग ग्रुप के साथ किया गया है।

सर्वेक्षण के मुताबिक 30 फीसद लोगों को यह लगता है कि त्वचा के रंग की वजह से भेदभाव किया जाता है। 18 फीसद लोगों का कहना है कि लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। 31 फीसद लोगों को लगता है कि भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भेदभाव एक बड़ी समस्या है। 53 फीसद इसे एक छोटी समस्या के रूप में देखते हैं और 17 फीसद इसे समस्या नहीं मानते हैं। 73 फीसद लोगों का मानना है कि एशियाई-अमेरिकी समुदाय के लोग जो भारतीय मूल के नहीं हैं, उन्हें भारतीय-अमेरिकी लोगों से ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ता है। 90 फीसद लैटिन अमेरिकन और 86 फीसद अफ्रीकन-अमेरिकी लोगों को भेदभाव का ज्यादा बड़ा शिकार मानते हैं।

गत वर्ष अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लायड की मृत्यु के बाद बड़े स्तर पर भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही हैं। रैलियों के दौरान कई बार प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच काफी टकराव भी देखने को मिलता है। कई बार पुलिस लाठीचार्ज भी करती है, लेकिन फिर भी अमेरिका में भेदभाव एक बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं नस्लीय भेदभाव अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बना। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नस्लीय हिंसा को भड़काने का आरोप भी लगा।

अमेरिकी राज्यों द्वारा कोरोना से जुड़े आंकड़े अपडेट करने में लेटलतिफी से हेल्थ एक्सपर्ट्स चिंतित

वाशिंगटन । अमेरिका में आधे राज्य ही कोविड-19 से जुड़े प्रतिदिन के आंकड़े बता रहे हैं। जिसमें नए मामले, एक्टिव केस मृत्यु और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी शामिल है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह ट्रेंड कुछ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को चिंतित कर रहा है। देश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर हो रही लेटलतिफी को लेकर चिंता बढ़ गई है। एक प्रमुख अमेरिकी मीडिया हाउस के हवाले से बताया कि इस सप्ताह दो सबसे बड़े स्केल-बैक प्रभावी हुए, जिसमें फ्लोरिडा में प्रति सप्ताह में एक अपडेट नहीं किया गया और और अलबामा में प्रति सप्ताह 2-3 बार अपडेट नहीं किया गया। अलबामा राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक स्वास्थ्य अधिकारी करेन लैंडर्स ने बताया कि राज्य में कोरोना के अपडेट को प्रकाशित करने के पीछे की वजह दैनिक मामलों, मौतों और अस्पताल में भर्ती होने में लगातार कमी के साथ किया गया है।

बाइडेन से मुलाकात से पहले बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 'अमेरिका-रूस के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर'

CREDITS: AP

वॉशिंगटन, एजेंसी । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन से 16 जून को होने वाली बैठक से पहले कहा कि अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर हैं. एनबीसी द्वारा प्रसारित पुतिन के एक अंग्रेजी इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी गई. पुतिन और बाइडेन अगले हफ्ते जेनेवा में मुलाकात करने वाले हैं. वहीं, बाइडेन ने ब्रिटेन पहुंचने पर कहा कि वह पुतिन से मुलाकात में दोनों मुल्कों के रिश्ते को लेकर स्पष्ट संदेश देने वाले हैं.

बाइडेन ने कहा कि हम रूस के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहते हैं. हम एक स्थिर और उम्मीद के मुताबिक संबंध बनाना चाहते हैं. लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि रूसी सरकार हानिकारण गतिविधियों में संलग्न होगी तो अमेरिका उसे एक मजबूत और सार्थक तरीके से जवाब देगा. पुतिन और बाइडेन के बीच ये पहली औपचारिक बैठक ऐसे समय पर हो रही है, जब वाशिंगटन और मॉस्को के बीच रिश्ते रूसी साइबर अटैक, एलेक्सी नवालनी की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों को लेकर बेहद खराब चल रहे हैं.

ट्रंप एक असाधारण और प्रतिभाशाली व्यक्ति-व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा भी की. पुतिन ने ट्रंप को एक असाधारण और प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया. वहीं, बाइडेन को मौलिक रूप से अलग व्यक्ति करार दिया. पुतिन ने कहा, खैर अब भी मेरा मानना है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक असाधारण व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो वे अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बने होते. आप भले ही उन्हें पसंद करें या न करें. लेकिन वह अमेरिकी राजनीति में लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन फिर भी वह ऊपर तक आए.

बाइडेन एक अलग तरह के व्यक्ति- पुतिन- रूसी राष्ट्रपति ने कहा, बाइडेन ट्रंप से मौलिक रूप से अलग हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन एक करियर मैन हैं. उन्होंने लगभग अपना पूरा वक्त राजनीति में बिताया है. उन्होंने कहा, वह एक अलग तरह के व्यक्ति हैं और मुझे आशा है कि इसके कुछ फायदे और नुकसान हैं. लेकिन मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कोई भी आवेग वाली कार्रवाई नहीं होगी. बाइडेन और पुतिन के बीच अगले हफ्ते होने वाली बैठक को लेकर माना जा रहा है कि इससे दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में सुधार हो सकता है.

चीनी हैकर्स ने बनाया रूसी सरकार की वेबसाइटों को निशाना, गोपनीय डेटा चुराने की कोशिश

मास्को । चीन के हैकर्स ने रूसी सरकार की वेबसाइटों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार गोपनीय सरकारी डेटा चोरी करने के उद्देश्य से रूसी सरकारी एजेंसियों की वेबसाइटों को हैक करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। अमेरिकी कंपनी सेंटिनलवन द्वारा यह रिपोर्ट पिछले महीने रूस की प्रमुख जासूसी एजेंसियों में से एक फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और टेलीकॉम फर्म रोस्टेलकॉम की साइबर यूनिट की तरफ से जारी एक रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे थंडरकैट्स ने रूसी सरकारी एजेंसियों की वेबसाइटों को हैक कर लिया। अमेरिकी कंपनी सेंटिनलवन के विशेषज्ञों ने कहा कि रूसी एजेंसियों पर हमला करने वाला हैकिंग टूल संदिग्ध चीनी जासूसों के एक व्यापक समूह से जुड़ा है, जिन्होंने हाल के वर्षों में एशियाई सरकारों को भी निशाना बनाया है। विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चीन के हैकर्स ने मैलवेयर विकसित किया है, जो एक डाउनलोडर प्रोग्राम है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है कि वर्तमान साइबर हमला अद्वितीय है और विशेषज्ञों द्वारा संघीय स्तर पर खतरे के रूप में इसका आकलन किया जा रहा है। ऐसा करने वालों ने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। यही नहीं हैकर्स ने एक साथ कई प्रकार के हमलों का इस्तेमाल किया। जैसे फिशिंग, वेब कमजोरियों का शोषण और ठेकेदारों के माध्यम से हमले किए गए। पिछले साल, अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से एक संदिग्ध चीनी हैकिंग अभियान का खुलासा किया ।

ब्रिटिश पीएम जॉनसन बोले- 18 महीनों में हुई गलती दोहराने से बचना होगा, कोरोना से सबक लेने का समय

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने महामारी से सीख लेने के संदेश के साथ कॉर्नवाल में शुक्रवार को जी-7 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया. जॉनसन ने आगाह किया कि 2008 की आखिरी बड़ी आर्थिक मंदी की भूल को दोहराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि उस समय समाज के सभी हिस्से में एक समान विकास नहीं रहा. जी-7 में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के साथ यूरोपियन यूनियन शामिल हैं.

शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए जॉनसन ने कहा कि यह देखना वाकई बहुत सुखद है कि पिछले साल महामारी के बाद से पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर कोई बड़ा आयोजन हो रहा है. भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को डिजिटल माध्यम से तीन सत्र को संबोधित करेंगे. जॉनसन ने उद्घाटन संबोधन में कहा, मुझे लगता है कि यह बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि हमें महामारी से सीख लेने की जरूरत है.

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वह गलती नहीं दोहराएं जो हमने पिछले 18 महीने में की और हमें अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए उपाय करने होंगे. उन्होंने कहा, इस महामारी के साथ क्या गलत हुआ है, जिसने इसे एक स्थायी निशान बना दिया है. असल में असमानताएं को वजह से स्थिति बिगड़ी. हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जैसे-जैसे हम उबर रहे हैं, हम अपने समाजों को ऊपर उठाएं.

हमें बेहतर निर्माण करने की जरूरत है. ब्रिटिश पीएम ने कहा, मैं वास्तव में सोचता हूं कि हमारे पास ऐसा करने का एक बड़ा अवसर है, क्योंकि जी-7 के रूप में हम एक स्वच्छ, हरित विश्व के लिए अपने दृष्टिकोण में एकजुट हैं.

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने जी-7 नेताओं से ऐसा क्या कहा कि जमकर लगे ठहाके? जानें क्या है मामला

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से दुनिया के सबसे बड़े इनडोर वृषावन में मुलाकात की. महारानी एलिजाबेथ ने 'ग्रुप ऑफ सेवन' या जी-7 के नेताओं के लिए एक रिसेप्शन का आयोजन किया. इस दौरान सभी नेताओं और महारानी एलिजाबेथ ने एक संयुक्त फोटो खिंचवाई. तस्वीर लेने से पहले महारानी एलिजाबेथ ने त्7 के नेताओं से कहा कि आप लोगों को ऐसा दिखना चाहिए कि आप लोग यहां का आनंद उठा रहे हैं. इसके बाद सभी नेता ठहाके लगाकर हंसने लगे.

गौरतलब है कि ब्रिटेन के कॉर्नवाल में शुक्रवार से तीन दिवसीय जी-7 सम्मेलन का आगाज हुआ. महारानी एलिजाबेथ के साथ ब्रिटिश शाही परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे. प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कमिला के अलावा प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट भी मौजूद रहीं. अप्रैल में प्रिंस फिलिप के दुखद निधन के बाद शाही परिवार का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था. महारानी एलिजाबेथ द्वारा इस रिसेप्शन का आयोजन ईडन प्रोजेक्ट में किया गया. इस जगह पर विशिष्ट बुलबुले वाले घर हैं, जिसमें पौधों की हजारों किस्में मौजूद हैं.

महारानी एलिजाबेथ वैश्विक नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बैठी. इस दौरान उन्होंने कहा, 'आपको ऐसा दिखना चाहिए जैसे आप आनंद ले रहे हैं?' ये सुनकर सभी नेता हंसने लगे. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जवाब दिया, 'हां हम लोग यहां का आनंद उठा रहे हैं.'

ये ऐसा पहला मौका था, जिसमें महारानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की. अपने 69 साल के शासनकाल में बाइडेन 13वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिनसे महारानी ने मुलाकात की है.

रविवार को विंडसर कैसल में होगी बाइडेन और महारानी की मुलाकात

वहीं, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने कहा, मैं और जो क्वीन से मुलाकात करने का इंतजार कर रहे हैं. ये हमारे दौरे का सबसे अच्छा हिस्सा होने वाला है. दरअसल, त्7 सम्मेलन खत्म होने के बाद रविवार को विंडसर कैसल में अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला महारानी से निजी तौर पर मुलाकात करने वाले हैं. बता दें कि जी-7 में दुनिया की सात विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं. जी-7 की पहली बैठक 1975 में हुई थी लेकिन तब सिर्फ 6 देश ही इसमें शामिल थे. 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद अब कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली इसमें शामिल हैं.

भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को मिला पुलित्जर पुरस्कार, दुनिया के सामने बेनकाब किया था चीन का बड़ा झूठ

वॉशिंगटन, एजेंसी । भारतीय मूल की पत्रकार मेघा रोजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है. उन्हें ये पुरस्कार दुनिया के सामने चीन के बड़े झूठ उजागर करने को लेकर मिला है. उनकी रिपोर्ट्स से पता चला था कि चीन उइगर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यक समूह के लोगों को यातना शिविरों में कैद करके रख रहा है. इसके लिए राजगोपालन ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया था. इन पुरस्कारों की घोषणा शुक्रवार रात को की गई है.

मेघा राजगोपालन ने अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में मिले इस पुरस्कार को इंटरनेट मीडिया बजफीड न्यूज के दो सहकर्मियों के साथ शेयर किया है. राजगोपालन और उनके सहकर्मियों ने यातना शिविरों में रहने वाले करीब दो दर्जन लोगों का साक्षात्कार लिया था. इन साक्षात्कारों की पुष्टि करने के लिए इन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों और 3डी सिमुलेशन का इस्तेमाल किया . वह कहती हैं, 'मैं पूरी तरह से हैरान थी, मैंने इसकी कल्पना नहीं की.' प्रकाशन के अनुसार, राजगोपालन और उनके सहकर्मियों एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशेक ने 260 यातना शिविरों की पहचान की थी.

कजाकिस्तान में लिए साक्षात्कार -इसके लिए इन्होंने एक बड़ा डाटाबेस तैयार किया था. वह चीन में भी साक्षात्कार लेना चाहती थीं, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली. जिसके बाद उन्होंने पड़ोस के कजाकिस्तान में शिविरों से भागकर आए लोगों से बात की. भारतीय मूल के एक अन्य पत्रकार नील बेदी को भी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है. उन्हें ये पुरस्कार स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में उनके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट्स के लिए मिला है. बेदी ने फ्लोरिडा में सरकारी अधिकारी के बच्चों की तस्करी को लेकर एक इनवेस्टिगेटिव स्टोरी लिखी थी, जो टांपा बेय टाइम्स में प्रकाशित हुई थी.

डार्नेला फ्रेजियर को भी मिला पुरस्कार- वहीं अमेरिका के अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करने वाली लड़की डार्नेला फ्रेजियर को भी पुरस्कार मिला है. उन्होंने मिनेसोटा में हुई इस घटना को रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद अमेरिका सहित दुनियाभर में नस्लीय हिंसा का विरोध करते हुए लोगों ने खूब प्रदर्शन किए थे. ये वीडियो क्लिप दुनियाभर में वायरल हो गई थी.

पुलिस की बर्बरता का भी खूब विरोध किया गया. इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक पुलिसकर्मी अपने घुटने से फ्लॉयड की गर्दन को दबा रहा है. फ्लॉयड ने कई बार कहा कि वह सांस नहीं ले पा रहे लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी ने उनकी एक नहीं सुनी थी.

'ट्रंप के सपने' को बाइडेन ने किया चकनाचूर! मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की परियोजना को झटका, फंड वापस लेंगे यूएस राष्ट्रपति

वाशिंगटन , एजेंसी । अमेरिका की सरकार ने शुक्रवार को एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीमा पर दीवार बनाने की विशिष्ट परियोजना के वित्तपोषण को नुकसान होने के साथ-साथ पर्यावरण नियमनों को दरकिनार कर तेजी से काम करने के लिए इसे मिला दर्जा भी खत्म हो जाएगा. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद संभालने के बाद उनके प्रशासन द्वारा परियोजना की समीक्षा किए जाने के बीच दीवार के निर्माण कार्य पर रोक लग गई थी.

अमेरिका की दक्षिण-पश्चिम सीमा से प्रवासियों के आने की आशंका के चलते संसद में रिपब्लिकन सदस्यों ने इस पर विरोध प्रकट किया था. परियोजना पूरी तरह खत्म नहीं की गई है लेकिन कांग्रेस में इसे अब भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जहां पूर्व राष्ट्रपति से करीबी तौर पर जुड़े कुछ रिपब्लिकन सांसद इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं . बाइडेन 2 अरब डॉलर से अधिक कोष को वापस करना चाहते हैं, जिसे ट्रंप प्रशासन ने दीवार के लिए पेंटागन के खर्च से आवंटित किया था.

कहां खर्च होगा पैसा- साथ ही शेष बची राशि को निर्माण के कारण उत्पन्न हुई, 'जीवन, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय समस्याओं' से निपटने के लिए खर्च किया जाएगा . प्रशासन ने सांसदों से अतिरिक्त धन मुहैया नहीं करने को भी कहा है क्योंकि बाइडेन की टीम का मानना है कि यह अनावश्यक प्रयास है. प्रबंधन और बजट कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'समूची दक्षिणी सीमा में विशाल दीवार का निर्माण और अमेरिकी करदाताओं के अरबों डॉलर को खर्च करना कोई गंभीर नीतिगत समाधान नहीं है और ना ही यह संघीय कोष का वाजिब इस्तेमाल है.'

क्यों बनाई जा रही दीवार- अमेरिकी सरकारें दशकों से अमेरिका-मेक्सिको की 3200 किलोमीटर सरहद पर दीवार और अन्य अवरोधक बना रही है ताकि देश में बिना जांच प्रवेश के कुछ आसान मार्गों को खत्म किया जा सके.

ट्रंप ने इस मुद्दे को अपनी राजनितक पहचान का केंद्र बना लिया था. ट्रंप प्रशासन ने करीब 725 किलोमीटर दीवार का निर्माण कराया था और परियोजना को पर्यावरण समीक्षा और मध्यस्थता के दायरे से बाहर रखा था.

बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई में मारे गए दो आतंकी, एक सैनिक की भी हुई मौत

इस्लामाबाद , एजेंसी। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार को की गई सैन्य कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए, जबकि मुठभेड़ में एक सैनिक की भी मौत हो गई. पाकिस्तान की सेना के मीडिया विभाग ने एक बयान में बताया कि खरान जिले के हलमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और इस दौरान फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के एक सैनिक की मौत हो गई. बयान में कहा गया कि हिंसा और आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में संलिप्त रहे दो आतंकवादी मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया. आतंकवादी और अलगाववादी आए दिन बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमले करते हैं और सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं. इसी महीने की शुरुआत में अलग-अलग हमले में चार सैनिक मारे गए थे और आठ जवान घायल हो गए थे.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ही शुक्रवार को तेज गति से जा रही एक बस के पलटने से 18 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए. मीडिया ने यह खबर दी. 'जियो न्यूज' के मुताबिक, बस वाध से दादू की तरफ जा रही थी और यह घटना प्रांत के खुजदार जिले के खोरी में हुई. मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद बचाव कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया. घायलों को टीचिंग हॉस्पिटल खुजदार ले जाया गया जहां तीन और लोगों की मौत हो गई और मृतक संख्या बढ़कर 18 हो गयी. घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर हैं. सूत्रों ने समाचार चैनल को बताया कि यात्री बस के तेज गति से चलने के दौरान ड्राइवर का वाहन पर संतुलन नहीं रहा और इस कारण यह हादसा हुआ.

व्हेल ने मछुआरे को निगला! फिर 'मौत को मात' देकर मछली के मुंह से जिंदा बाहर आया शख्स, कहानी सुन दुनिया हैरान

दुनिया की सबसे बड़ी मछली मानी जानी व्हेल के आकार को देखते हुए कहा जाता है कि ये इंसानों को निगल सकती हैं. अमेरिका में हुई एक घटना ने इस बात को सच साबित भी कर दिया है. दरअसल, एक अमेरिकी मछुआरे का कहना है कि उसे हंपबैक व्हेल ने निगल लिया था. लेकिन वह उसके मुंह से बाहर निकलने में कामयाब रहा और लोगों को अपनी ये कहानी बताई. मछुआरे का कहना है कि एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूं. वहीं, अब जो भी इस कहानी को सुन रहा है वो हैरान रह जा रहा है.

माइकल पैकार्ड ने व्हेल द्वारा निगले जाने के बाद जिंदा बचने को लेकर अपने फेसबुक पर लिखा, 'मैं व्हेल के मुंह में करीब 30 से 40 सेकेंड तक रहा, इसके बाद वह सतह की ओर आई और उसने मुझे अपने मुंह से बाहर थूक दिया.' उन्होंने कहा, 'एक हंपबैक व्हेल ने मुझे खाने की कोशिश की. मुझे चोटें आई हैं, लेकिन मेरी एक भी हड्डी नहीं टूटी है.' पैकार्ड ने स्थानीय अखबार कैप कोड टाइम्स को बताया कि जब वह मैसाचुसेट्स के तट से दूर लोबस्टर पकड़ने के लिए डुबकी लगा रहे थे, तभी पानी में नीचे मौजूद व्हेल ने उन्हें निगल लिया. उन्होंने बताया कि अचानक से मैंने एक विशाल झटके को महसूस किया. इसके बाद मुझे याद है कि पूरी तरह से अंधेरा छा गया.

कुछ इस तरह का था मंजर- पैकार्ड ने बताया कि सतह से 10 मीटर नीचे हुई इस घटना को लेकर उन्हें लगा कि उन पर एक शार्क ने हमला किया है. लेकिन जब मुझे कम दांतों का आभास हुआ और चोट के कम निशान दिखे तो मुझे लगा कि माजरा कुछ और है. उन्होंने कहा कि मैंने उसके मुंह के भीतर हलचल की ताकि मैं बाहर निकल सकूं. मैंने रोशनी देखी और मैं अपना सिर उस ओर बढ़ाने लगा, फिर कुछ सेकेंड के भीतर ही मैं पानी में था, क्योंकि व्हेल ने मुझे बाहर निकाल दिया था. पैकार्ड के साथी ने कहा कि उन्होंने पानी के भीतर धमाका होता हुए देखा, जब व्हेल ने सतह पर आकर हलचल की. फिर उन्होंने पैकार्ड को देखा.

इस वजह से पैकार्ड को व्हेल ने निगला- मैसाचुसेट्स के प्रोविंसटाउन में सेंटर फॉर कोस्टल स्टडीज में हंपबैक व्हेल अध्ययन की निदेशक जूक रॉबिंस ने कहा कि उनके पास इस मामले पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता था कि यह महज एक मजाक है क्योंकि कि मैं इसमें शामिल लोगों को जानती हूं. ऐसे में मेरे पास इस मामले पर यकीन करने वाला हर कारण मौजूद है. रॉबिंस ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस तरह की घटना के बारे में नहीं सुना है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि पैकार्ड गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे. हंपबैक व्हेल मुंह खोलकर बड़ी मात्रा में पानी को अपने मुंह के भीतर भरती हैं. इसी वजह से पैकार्ड उसके मुंह में फंस गए होंगे.

कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को युद्धस्तर पर तैयारी कर रही सरकार : सीएम केजरीवाल

नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आगाह किया कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका प्रबल है. सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है. केजरीवाल ने कहा कि दूसरी लहर में दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिली थी. संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए लगातार तैयारियां कर रही है. इसी के तहत दिल्ली सरकार के 9 अस्पतालों में आज 22 ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई. जिनसे 17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल सकेगी. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वीडियो लिंक के ज़रिए इसकी शुरुआत की.

सीएम ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर पर ब्रिटेन से संकेत मिल रहे हैं. 45 प्रतिशत तक टीकाकरण के बावजूद वहां मामले बढ़ रहे हैं. इसलिए हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं. केजरीवाल एक ऑनलाइन कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसमें उन्होंने दिल्ली के नौ अस्पतालों में 22 नए पीसीए ऑक्सीजन संयंत्रों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. उन्होंने कहा, ''दिल्ली के नौ अस्पतालों में आज लगाए गए ये नए ऑक्सीजन संयंत्र कोविड-19 से लड़ने में हमारी तैयारियों को मजबूती देंगे.''

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगाह किया कि ''कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आने की संभावना प्रबल है.'' उन्होंने कहा, ''हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते और हमारी सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है.'' केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर के मामले में कोविड-19 से निपटने के लिए ऑक्सीजन टैंकर भी खरीद रही है. उन्होंने कहा, ''दिल्ली के लोग कोविड की दूसरी लहर से निपटने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उद्योग क्षेत्र के प्रति भी हम आभारी हैं.''

दिल्ली को फिर से मिलकर लड़ना होगा- केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक साथ मिलकर कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना संघर्ष और अनुशासन से किया तथा ''इसे काबू करने में सफल हुए.'' उन्होंने कहा, ''हम प्रार्थना करते हैं कि कोविड की तीसरी लहर हमें प्रभावित न करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दिल्ली को फिर से मिलकर लड़ना होगा.'

नई दिल्ली में यमुना खादर मयूर विहार के पंचशील शिक्षण संस्थान में एक झोपड़पट्टी क्षेत्र के छात्र एक ओपन-एयर ट्यूशन क्लास में भाग लेते हुए।

संक्षिप्त खबर

दिल्ली मंडल के 8 स्टेशनों पर फिर शुरू हुई प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, जानिए कितने रखे गये इसके दाम?

नई दिल्ली । दिल्ली में कोरोना से हालात अब तेजी से सुधार रहे हैं. दिल्ली में भी कुल संक्रमित मरीजों की संख्या भी अब 4,000 से नीचे रह गई है. ऐसे में रेलवे ने भी अब दिल्ली मंडल के आठ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री फिर से शुरू कर दी है. उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद रेलयात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री करने का निर्णय लिया गया है. फिलहाल दिल्ली मंडल के 8 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री फिर से शुरू की गई है. महाप्रबंधक ने बताया कि स्टेशन पर भीड़ भाड़ अधिक ना हो इसको लेकर प्रति प्लेटफार्म टिकट का मूल्य भी ?30 रहेगा. रेलयात्री अब फिर से नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार रेल टर्मिनल, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली छावनी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं. महाप्रबंधक गंगल का कहना है कि अभी यह सुविधा उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के 8 प्रमुख स्टेशनों पर ही शुरू की जा रही है, बाकी अन्य स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री का निर्णय मांग के अनुसार लिया जाएगा. बताते चलें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रेलवे की ओर से सभी प्लेटफार्म पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थाई रूप से बंद कर दी गई थी जिससे स्टेशनों पर उमड़ने वाली अनावश्यक भीड़ को रोका जा सके.

दिल्ली के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में दुकान में लगी आग, 16 दमकल गाड़ियां बुझाने पहुंचीं

नई दिल्ली । राजधानी के लाजपत नगर इलाके में आज सुबह कपड़ों की दुकान में आग लग गई. सुबह करीब 10 बजे के आसपास दुकान में आग लगते ही बाजार में अफरा-तफरी मच गई. फौरन दमकल विभाग को सूचना दी गई. आग बुझाने के लिए जल्द ही 16 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. खबर मिलने तक आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट के ब्लॉक-1 में मौजूद दुकान में आग लगी है. आग की लपटें इतनी विकराल हैं कि इस बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मियों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. बताया जा रहा है कि आग कपड़े के एक शोरूम में लगी है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है. दमकल विभाग के कर्मचारी जल्द से जल्द आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं. आग लगने के बाद लाजपत नगर मार्केट के स्थानीय दुकानदारों ने पहले इसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते लपटों ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया.

ये सभी दमकल आग बुझाने में जुटे हैं- इसी बीच दमकल विभाग को सूचना दी गई. जानकारी के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलने पर विभाग के 16 दमकलों को मौके के लिए तुरंत रवाना किया गया. सेंट्रल मार्केट में ये सभी दमकल आग बुझाने में जुटे हैं.

छह गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया था- बता दें कि बीते 17 मई को देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में दो मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में रविवार देर रात आग लग गई थी. हालांकि, वहां रहने वाले एक परिवार के सभी पांच सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया था. दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें देर रात एक बजकर 24 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी. और दमकल विभाग की छह गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया था.

प्रेमी ने कहा- सुशांत राजपूत आत्महत्या कर सकता है, तो तुम भी कर लो! युवती ने फंदा लगाकर दे दी जान

गुरुग्राम। आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकता है तो तुम भी कर लो. इसके बाद 22 वर्षीय दीक्षा नाम की युवती ने सेक्टर 14 के सनशाइन होटल में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली. ये गंभीर आरोप मृतका दीक्षा के पिता ने गुरुग्राम पुलिस को दी शिकायत में दर्ज करवाया गया है. पुलिस को दी शिकायत में दर्ज करवाया गया कि कैसे आरोपी निशांत झा ने उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर दीक्षा के साथ बार बार दुष्कर्म किया .और जब दीक्षा गर्भवती हो गई तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया. बहरहाल, गुरुग्राम पुलिस ने मृतका दीक्षा के पिता की शिकायत पर सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है. दिल्ली की रहने वाली दीक्षा को निशांत झा ने पहले अपने प्यार में फंसाया और फिर उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा. इसी के चलते जब दीक्षा गर्भवती हो गयी तो निशांत झा ने दीक्षा से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया. एफआईआर में कहा गया है कि आत्महत्या से पहले यानी 5 दिसंबर को दीक्षा जल्द घर आने की बात कह घर से निकली तो थी लेकिन फिर कभी वापिस नही लौटीं. वही इस मामले पर एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की मानें तो पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म और 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. बहरहाल मामले की तफ़्तीश की जा रही है.

एनसीआर का पहला मामला नहीं- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और आत्महत्या का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दर्जनों ऐसे केस दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न थानों में दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे है.

पीएमओ में तैनात आईएफएस बता करता था ठगी, नीली बत्ती की गाड़ी से जमाता था रौब

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मेक इन इंडिया के तहत ठेका देने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को आईएफएस अधिकारी बताकर एक कारोबारी से 2.39 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। आरोपी बैठक करने के लिए नीली बत्ती की गाड़ी से अशोका होटल आता था। आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर के सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान सेक्टर 47 नोएडा निवासी पीयूष गोपाल बंधोपाध्याय(51) के रूप में हुई है। एक कंपनी के निदेशक दया शंकर मिश्रा ने वर्ष 2021 में शाखा में ठगी की शिकायत की। जिसमें बताया कि पीयूष गोपाल से उसकी मुलाकात वर्ष 2014 में हुई थी। उसने मेक इन इंडिया के तहत ठेका दिलाने की बात कहकर उससे मिलना जुलना शुरू किया।

केंद्र सरकार पर बरसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री, कहा-जहां स्कूलों में चल रही शराब की फैक्ट्रियां, वो हैं नंबर वन स्कूल

नई दिल्ली । दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर दिल्ली सरकार लगातार उदाहरण देती रही है. लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को बेकार बताते हुए देश में नंबर 1 सरकारी स्कूलों में पंजाब राज्य को यह तमगा दिया है. इसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार और पंजाब सरकार पर निशाना सोते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की ओर से गत दिनों जारी किए गए रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पंजाब के खस्ताहाल पड़े सरकारी स्कूलों को देश में नंबर वन बताया गया है. जबकि यहां के स्कूलों में शराब की फैक्ट्रियां चलती पाई गई हैं. वहीं, 2 से 3 सालों में 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा है. उस राज्य के स्कूलों को नंबर वन बताया जा रहा है जोकिपंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार और पंजाब की कैप्टन सरकार की जुगलबंदी को दिखाता है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में पंजाब के खस्ताहाल पड़े सरकारी स्कूल जिनमें न बुनियादी ढांचे है और न ही बुनियादी सुविधाएं उन्हें शानदार बता रही है और दिल्ली के स्कूलों को बेकार बता रही है. ये रिपोर्ट पंजाब के चुनाव से पहले कैप्टन सरकार को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में मिला है. पंजाब के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के बारे में बताते हुए सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में न पढ़ाई हो रही है, न ही उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने पर कोई काम किया गया है. लेकिन मोदी जी कैप्टन सरकार की नाकामियों पर अपनी रिपोर्ट के द्वारा पर्दा डालने का प्रयास कर रहे है. सरकारी स्कूलों के बदतर हालात के कारण पंजाब में अभिभावकों को अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है. हालात ये है कि पंजाब के सरकारी स्कूल में शराब की फैक्ट्री पाई गई हैं.

दिल्ली पुलिस के 2असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर्स पर हमले को लेकर राकेश टिकैत का अजब बयान

नई दिल्ली । पिछले साढ़े छह महीने से तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर सिंघु बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शनिवार को नया ट्विस्ट आ गया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के दो के साथ मारपीट हुई है। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने त्वरित प्रतिक्रिया में कहा कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहे होंगे, इसलिए ऐसा हुआ।

आरोपों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के दो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर्स जब सिंघु बॉर्डर पर तस्वीरें खींच रहे थे, तभी कथित रूप से कुछ आंदोलनकारी किसानों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। पिटाई का यह तथाकथित पूरा मामला 10 जून का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिंघु बॉर्डर पर दोनों पुलिसकर्मी फोटो खींच रहे थे। आरोप है कि आपत्ति के बाद कुछ किसानों ने दोनों पर हमला बोलते हुए पीट दिया। इस बाबत पीड़ितों की ओर से नरेला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

उधर, मामला मीडिया में सामने आया तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर अजब बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि वे (पुलिसकर्मी) सिविल ड्रेस में होंगे, उनको लगा होगा कि चैनल के लोग हैं और हमें गलत तरह से दिखाते हैं। हमारे लोग हिंसा नहीं करते। इस बयान से यह भी साफ हो रहा है कि किसान प्रदर्शनकारियों ने मीडियाकर्मी समझकर पुलिसवालों पर हमला किया। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या सिंघु बॉर्डर पर मीडियाकर्मी निशाने पर थे। उधर, भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस और सरकार तो चाहती है कि हम किसानों के साथ पंगेबाजी करें। वहीं, दर्ज मामले के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के दो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर्स ने 10 जून को सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल की तस्वीरें खींची। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह ने उन पर कथित रूप से हमला किया। उधर, किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को देशभर में राजभवनों पर धरना देने का प्लान बनाया है। संयुक्त किसान मोर्चा शुक्रवार को कहा कि वे 26 जून को प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजेंगे। एसकेएम के किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस दिन को 'खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

दिल्ली मास्टर प्लान-2041 : लीक से हटना बेहद जरूरी, तभी शहर की जरूरतें होंगी पूरी

नई दिल्ली । दिल्ली फिलवक्त सघन बसावट वाला शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां एक वर्ग किमी में 11,320 लोगों की रिहायश है। आने वाले वक्त में क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं, लेकिन आबादी दिल्ली की तेजी से बढ़ रही है। 2040 तक दिल्ली की आबादी तीन करोड़ के करीब पहुंच जाएगी, 2011 में जो 1.13 करोड़ थी। दिल्ली का करीब 75 फीसदी हिस्सा यानि 1483 वर्ग किमी शहरी है। बढ़ती आबादी की चुनौतियों का माकूल समाधान करने के लिए डीडीए ने मास्टर प्लान 2041 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पर आ रही प्रतिक्रियाएं काफी उत्साहवर्धक हैं। विशेषज्ञों समेत आम लोगों की राय है कि दिल्ली की बसावट का इस तरह से नियोजित किया जाना चाहिए, जिससे आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं हासिल हो सकें। विशेषज्ञ रेंटल हाउसिंग समेत ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलेपमेंट (टीओडी) सरीखी परियोजनाएं युद्धस्तर पर लागू करने की सलाह दे रहे हैं।

इससे करीब तीन करोड़ की आबादी को छह मुहैया कराना आसान होगा। इसके साथ स्लम और अनाधिकृत कालोनियों को दोबारा नए सिरे से विकसित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम करने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अनाधिकृत कालोनियों का नए सिरे से विकास किया जाए तो मेट्रो और रेल लाइन के नजदीक के इलाकों को भी विकसित कर सभी वर्गों के लिए रिहायश की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।

विशेषज्ञों ने कहा...

दिल्ली की आबादी में बढ़ोतरी के बाद 20 साल बाद आंकड़ा तीन करोड़ से अधिक होगी। इससे और अधिक मकानों की जरूरत होगी जबकि अनाधिकृत कालोनियों और स्लम को नए सिरे से विकिसित करना होगा। इसके लिए रेंटल हाउसिंग परियोजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बढ़ावा देने से रिहायशी की कमी दूर होने के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर होंगी। जापान में अभी भी रेंटल हाउसिंग का प्रचलन है, जिसे अपनाने से मौजूदा संसाधनों के साथ ही दिल्ली को नई शक्ल दी जा सकती है। रेंटल हाउसिंग परियोजना के तहत सरकारी जमीन पर निजी क्षेत्र के सहयोग से हाउसिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे कम जगह में अधिक लोगों के लिए रहने की सुविधा होगी।

स्लम की बजाय बहुमंजिला इमारतें बनाई जा सकती है। अनाधिकृत कालोनियों की बजाय छोटे छोटे टाउनशिप को अमली जामा पहनाने से लोगों को सेक्टरों की तरह मॉल्स, दुकानें, क्लब, चिकित्सा सुविधाओं के लिए नए निर्माण किए जा सकते हैं। इससे लोगों को जहां बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी तो दूसरी तरफ सरकार को भी वाणिज्यिक परिसरों से आय होगा। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में रहने वालों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को विस्तार देते हुए नया कानून बनाने से भी काफी हद तक संभावित परेशानियों को दूर किया जा सकता है।

नई दिल्ली में लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट इलाके में एक शोरूम में आग बुझाने का प्रयास करते दमकलकर्मी।

दिल्ली में शुरू हुआ पहला ग्रीन हाउस, औषधीय पौधे तैयार करने को सभी नर्सरीज में बनेंगे ऐसे ग्रीन हाउस!

नई दिल्ली, (एजेंसी) ।

आधुनिक तकनीक से औषधीय पौधों को विकसित करने के लिए आईटीओ नर्सरी में वन विभाग का पहला ग्रीन हाउस तैयार किया गया है. लोग नर्सरी से पौधे लेने आ रहे हैं. इसलिए कम समय में अधिक पौधे विकसित करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया गया है. दिल्ली सरकार की ओर से तैयार किए गए इस ग्रीन हाउस का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया. बताते चलें कि प्रदूषण के खिलाफ सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत 5 जून से दिल्ली की 14 नर्सरी से निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है. यहां से आरडब्ल्यूए, एनजीओ समेत विभिन्न संगठनों और लोगों को निःशुल्क औषधीय पौधे वितरित किए जा रहे हैं.

पर्यावरण मंत्री राय का कहना है कि दिल्ली में अब ज्यादातर लोगों का पर्यावरण के प्रति रूझान बढ़ रहा है और विभिन्न संगठन और लोग दिल्ली सरकार की नर्सरी से पौधे लेने के लिए आ रहे हैं. पिछले साल भी लोगों ने दिल्ली सरकार की नर्सरी से करीब 7 लाख औषधीय पौधे लेकर अपने घरों में लगाए थे. हमारी कोशिश है कि नर्सरी में जल्दी-जल्दी पौधे तैयार हों, जिसके लिए यह ग्रीन हाउस शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे दिल्ली सरकार अपनी सभी नर्सरी में ग्रीन हाउस तैयार करेगी.

इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं औधषीय पौधे - पर्यावरण मंत्री का कहना है कि यह औधषीय पौधे इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं. ये पौधे इम्युनिटी बढ़ाने का काम करते हैं. यदि यह औधषीय पौधे हमारी रोज की जिंदगी में शामिल कर लिए जाएं, तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा. इसीलिए हम लोग ग्रीन हाउस को भी विकसित कर रहे हैं, ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में औधषीय पौधे तैयार कर पाएं.

कोरोना की थर्ड वेव: बच्चों को बचाने की WCD की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बनाया ये प्लान!

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव में बच्चों को कोरोना की चपेट में आने से बचाने और आने के बाद उनके इलाज के बेहतर इंतजाम करने के लिये दिल्ली सरकार के अलग-अलग मंत्रालय अपने तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं. दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग भी बड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है. महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें हर तरह की तैयारियां करनी होगी, क्योंकि संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर होने की आशंका है.

बताते चलें कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, अस्पतालों के निदेशक व समाज कल्याण विभाग के निदेशक के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर रिव्यू भी कर चुके हैं. उन्होंने दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए थे. मीटिंग में स्वास्थ विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी एस एम अली के अलावा समाज कल्याण विभाग के निदेशक, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जीटीबी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के निदेशक भी मौजूद रहे.

अनाथ, बेघर और दिव्यांग बच्चों का आंकड़ा होगा तैयार -महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार के संस्थानों में रह रहे अनाथ, बेघर और दिव्यांग बच्चों का आंकड़ा तैयार करके एनजीओ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से उनको सुरक्षा के दायरे में लाना होगा. इस काम में महिला एवं बाल विकास विभाग को एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करके सभी बाल गृहों, एनजीओ और ऑब्जर्वेशन होम के बीच में समन्वय स्थापित करना होगा.

जिलेवार सर्वे करा कर बच्चों का असल आंकड़ा पता लगाने के निर्देश- मंत्री का कहना है कि ऐसे बच्चे जिनके दोनों या दोनों में से एक माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनका असल आंकड़ा जानने के लिए स्वास्थ विभाग की मदद ली जानी चाहिए. महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक का कहना है कि यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग से मांगा जा रहा है, ताकि जिलेवार सर्वे करा कर ऐसे अनाथ, बेघर और दिव्यांग बच्चों का असल आंकड़ा पता किया जा सके.

कोरोना थर्ड वेव की आशंका, जिलों के कोविड केयर सेंटर बनने लगे अब चाइल्ड केयर सेंटर मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों का भी पता लगाया जाना चाहिए, जिनके माता-पिता की मृत्यु रिकॉर्ड में नहीं आ पाई है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग दिल्ली के सभी शवदाह गृह से आंकड़ा लेकर उसको शामिल करें.

अस्पतालों में तैयार किए जा रहे बच्चों के हिसाब से वेंटिलेटर, मास्क - स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों में बच्चों के हिसाब से वेंटिलेटर, मास्क आदि तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अस्पतालों में बच्चों के साथ उनके माता-पिता और यहां एक अटेंडेंट के ठहरने की व्यवस्था के प्रावधान भी किए जा रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि बच्चों को तीसरी लहर से सुरक्षित रखने के लिए ऐसे माता-पिता का टीकाकरण अनिवार्य है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या टीकाकरण की आयु से कम हैं.

चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन में होगी प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत- चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए. साथ ही, तीसरी लहर की रोकथाम के लिए भी व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है.

चाइल्ड केयर में मोबाइल यूनिट के इस्तेमाल जरूरत- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन को चिकित्सा सुविधा देने के लिए मोबाइल यूनिट का इस्तेमाल किया जा सकता है और सभी बाल गृहों में बच्चों की देखरेख कर रहे स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने की भी जरूरत है.

संपादकीय

टीकाकरण की बदलिए रणनीति

दुनिया में वैक्सीन के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में प्रतिष्ठित भारत कोविड-19 की इस घातक दूसरी लहर में अपनी योग्य आबादी के टीकाकरण के लिए संघर्ष कर रहा है। कोरोना की यह लहर न सिर्फ लोगों की जान ले रही है, बल्कि उनकी आजीविका को भी लील रही है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिसमें कुछ महीने पहले सुधार के संकेत दिखे थे। देश में दो टीकों की मंजूरी और संक्रमण के मामले में सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के कारण साल 2021 की एक आशाजनक शुरुआत हुई थी। लेकिन अब हम दुनिया में सबसे अधिक कोविड मामलों से मुकाबिल हैं, और इससे भी अहम बात यह है कि इस बार मौत का आंकड़ा काफी बढ़ गया है। पहली लहर में वायरस ने अमूमन बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को अधिक निशाना बनाया था, लेकिन इस बार इसने नौजवानों की भी जान ली है। मरने वाले 20 फीसदी लोगों की उम्र 45 साल से कम है। यह टीकाकरण की हमारी रणनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। जनवरी के मध्य में जब भारत ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी, तब हमने उम्र-आधारित रणनीति अपनाई और अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया। 1 फरवरी से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, 1 मार्च से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए और 1 मई से 18 साल व इससे अधिक उम्र के लिए टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की गई। हालांकि, हमें जल्द ही यह एहसास हो गया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वयस्क आबादी को टीका लगाने के लिए टीके की जितनी खुराक चाहिए, उतनी हमारे पास नहीं है। सरकार का अनुमान है कि इसके लिए 2.2 अरब खुराक की जरूरत है, जो दिसंबर तक तैयार की जा सकती है। पर कई लोग इसे अति-महत्वाकांक्षी और सच से मुंह फेरने जैसा आकलन बता रहे हैं। निजी क्षेत्र का मानना है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक-वी, जाइकोव-डी, नोवावैक्स व जेऐंडजे मिलकर दिसंबर, 2021 तक आधा या लगभग 1.2 अरब खुराक ही पूरी कर सकते हैं, जबकि फाइजर, स्पूतनिक और मॉडर्ना से संभवतः 10-20 करोड़ खुराकें आयात की जा सकती हैं। इससे ज्यादा तो कतई संभव नहीं है। ऐसे में, हमारी चुनौती टीकाकरण की ऐसी रणनीति तैयार करने की है, जो न सिर्फ जोखिम वाले लोगों की जान बचाए, बल्कि संक्रमण के प्रसार पर भी लगाम लगाए। अंतिम जनगणना के मुताबिक, 63 फीसदी आबादी 18 वर्ष से अधिक उम्र की है, और इसीलिए वह टीकाकरण के योग्य है। इसका मतलब है कि हमें देश भर में लगभग 82 करोड़ लोगों को टीका लगाने की जरूरत है। अगर हम मान लें कि 18 करोड़ लोगों ने टीके की कम से कम एक खुराक ले ली है, तब भी 64 करोड़ लोग अभी टीके से दूर हैं। चूंकि 'हर्ड इम्युनिटी' के लिए 70 फीसदी आबादी को टीके की दोनों खुराकें लगनी चाहिए, इसलिए अब करीब 45 करोड़ लोगों का टीकाकरण जरूरी है, जिसके लिए, हमें 90 करोड़ खुराक की दरकार है। इसीलिए, मौजूदा उत्पादन से भी हम साल के अंत तक सुरक्षित स्थिति में पहुंचने और तीसरी लहर को टालने में मदद कर सकते हैं। और, जनवरी 2022 से हम 20 करोड़ मासिक के हिसाब से बूस्टर डोज देना भी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह, अगर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टीके की एक भी खुराक बरबाद न हो, तो हमें इसके भंडारण, ढुलाई आदि की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी, और यह तभी हो सकता है, जब केंद्रीय व्यवस्था के उलट यह जिम्मा राज्यों को दिया जाए। अभी केंद्र सरकार ने एक मॉडल की घोषणा की है, जिसमें 50 फीसदी खरीद केंद्र करेगा, जबकि शेष राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र। निश्चय ही, राज्यों में टीके की खरीद और साझा जिम्मेदारियों के साथ उसके वितरण संबंधी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का यह मॉडल टीकाकरण को कारगर साबित हो। जरूरत महामारी विज्ञान के हिसाब से टीकाकरण को आगे बढ़ाने की भी है। जब टीके कम हों, तब न्यायसंगत वितरण के बजाय हमें उसका इस तरह बंटवारा करना चाहिए कि वह अधिक से अधिक प्रभावी साबित हो। जैसे, हमें जिलावार जनसंख्या घनत्व, संक्रमण के मामले, मृत्यु दर और दोगुने होने की दर जैसे मानकों के आधार पर टीकाकरण की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। इसके बाद जोखिम और संक्रमण के हिसाब से जिस व्यवसाय का खतरा ज्यादा है, उसके कर्मियों को तवज्जो देनी चाहिए। यदि हम कर्नाटक को एक उदाहरण मानें, तो बेंगलुरु को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, जिसके बाद मैसूर, बेल्लारी, दक्षिण कन्नड़ जिले, धारवाड़ जैसे इलाके होंगे। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद का नंबर पहले आएगा। पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, पटियाला जैसे इलाकों को प्राथमिकता मिलेगी। कर्नाटक में 50 फीसदी टीके बेंगलुरु और शेष टीके तेज संक्रमण वाले जिलों में भेजना सही रणनीति होगी। हर व्यक्ति को कम से कम एक खुराक देने के लिए कर्नाटक को अगले तीन माह तक 50 लाख खुराक प्रति महीने के हिसाब से टीके चाहिए। इससे हम संक्रमण का प्रसार थाम सकते हैं। एक महीने में 50 लाख खुराक देने के लिए हमें राज्य में रोजाना 1.5 लाख टीकाकरण करना होगा। अगर बेंगलुरु को हर महीने 25 लाख लोगों को टीका लगना है, तो वहां 500 टीकाकरण केंद्र की जरूरत होगी, जहां हर दिन 100-250 खुराकें बांटी जाएं। मलिन बस्तियों, स्थानीय बाजारों और निर्माण स्थलों में प्रतिदिन 1,000 खुराक लगाने के लिए सामूहिक टीकाकरण शिविर भी लगाए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ टीकाकरण में तेजी आएगी, बल्कि टीके को लेकर लोगों की झिझक भी कम होगी। व्यवसाय आधारित वर्गों में डिलिवरी करने वाले कर्मी, कैब ड्राइवर, दुकानदार, दुकान-कर्मचारी, निर्माण-कार्य से जुड़े मजदूर आदि को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके बाद ऊंची-ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग, गेटेड सोसाइटी और फिर बिल्डर फ्लैट में अकेले रहने वाले लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। एक बार जब शहर सुरक्षित हो जाएं, तब उसके बाद शहरों में आने-जाने वाले रास्तों पर, और अंत में राज्य के बाकी हिस्से में सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा सकता है। यह मॉडल पूरे देश में अपनाया जा सकता है। टीके की कमी को देखते हुए हमें टीकाकरण के लिए लक्षित प्राथमिकता तय करनी होगी। यही अभी की सही रणनीति होगी।

प्रवीण कुमार सिंह

दवा निर्माण के कच्चे माल पर घटे विदेशी निर्भरता, एपीआइ का उत्पादन बढ़ाने को मिले प्रोत्साहन

> इसी प्रकार, चिकित्सा उपकरण पार्क को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार चार चिकित्सा उपकरण पार्क में से प्रत्येक के लिए अधिकतम सौ करोड़ रुपये या साझा ढांचागत संरचना सुविधाओं के निर्माण की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत , या फिर इनमें जो भी कम हो, एकमुश्त अनुदान के रूप में देगी। इसके अलावा, सरकार ने 2020-21 से 2025-26 तक 3,420 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है।

यह सर्वविदित है कि दवा निर्माण के लिए कच्चे माल के मामले में भारत विदेश पर निर्भर है। कोरोना संक्रमण काल में इसने कई तरह की नई समस्याओं को भी पैदा किया है। दरअसल कुछ वर्ष पहले चीन ने रेयर अर्थ मेटल जिस पर दुनिया के ग्रीन तकनीक का भविष्य निर्भर करता है, उसका वैश्विक निर्यात मनमाने तरीके से रोक दिया था। चूंकि दुनिया के रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक चीन ही है, इसलिए उसने अपनी इस स्थिति का लाभ उठाया था। बात जब वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार को बाधा पहुंचाने के नाम पर विश्व व्यापार संगठन में पहुंची और उसने चीन को ऐसा संरक्षणवादी आचरण करने से मना किया तो चीन ने विश्व व्यापार संगठन की बात को भी ठुकरा दिया।

यह उदाहरण सिद्ध करता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में राज करने वाले देश ऐसा कर विश्व समुदाय से सौदेबाजी करने से नहीं चूकते। डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे रेयर अर्थ मेटल के जरिये चीन रक्षा, तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आपूर्ति मामले में राज करता है, वहीं नीयोडिमियम और प्रेसियोडीमियम जैसे रेयर अर्थ मेटल जो मोटर्स, टरबाइन और मेडिकल डिवाइस बनाने के काम आते हैं, उनकी आपूर्ति प्रणाली पर भी चीन का नियंत्रण है। ऐसा ही हाल एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआइ के मामले में भी है, जहां चीन का वैश्विक दबदबा बरकरार है। एपीआइ को ही बल्क ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। अगर भारत के एपीआइ के कुल आयात की बात करें तो अमेरिका से चार प्रतिशत, इटली से तीन प्रतिशत, सिंगापुर और हांगकांग से दो-दो प्रतिशत आयात करता है। वहीं चीन पर अपने करीब 70 प्रतिशत एपीआइ आयात के लिए भारत निर्भर है। ये तब है जब मात्रा की दृष्टि से भारत विश्व के कुल

जेनेरिक (सस्ते) मेडिसिन में 20 प्रतिशत का योगदान करता है और विभिन्न वैक्सीन की वैश्विक मांग की 60 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति करता है। भारत विश्व भर में बड़े पैमाने पर एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स की भी आपूर्ति करता है। ब्रिटेन की 25 प्रतिशत दवाइयों की मांग को पूरा करता है। अमेरिका में उपयोग में लाई जाने वाली तीन पिल्स में से एक भारत से ही भेजी गई होती है। इन सबके बावजूद भारत का एपीआइ आयात लगातार बढ़ता रहा है। वर्ष 2012 से 2019 के बीच यह 8.3 प्रतिशत के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत 15 अति आवश्यक दवाइयों के कच्चे माल के लिए चीन पर अति निर्भर है। भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्यात्मक दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1438.9 करोड डॉलर मूल्य की दवाओं का निर्यात किया और इसी वित्तीय वर्ष में 356 करोड़ डॉलर मूल्य के बल्क ड्रग्स का आयात किया जिसमें चीन से 240 करोड़ डॉलर मूल्य का आयात शामिल था। इस मामले में चीन से इस अवधि में किया गया आयात कुल आयात का 67.5 प्रतिशत था। चीन से बल्क ड्रग यानी एपीआइ आयात करने की प्रमुख वजह कम कीमत है। वहां से आने वाली बल्क ड्रग की कीमत दूसरे देशों को तुलना में 30 से 35 प्रतिशत कम होती है और एंटीबायोटिक या कैंसर के इलाज की दवाओं के मामले में तो भारत चीन पर ज्यादा निर्भर है। डायबिटीज, ब्लड-प्रेशर, थायराइड, गठिया, वायरल इंफेक्शंस आदि के लिए कच्चा माल या फिर कई प्रकार के सर्जिकल औजार और मेडिकल मशीनें, चीन से भारत आयात होने वाले फार्मा उत्पादों की सूची लंबी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में पेनसिलिन और ऐजिथ्रोमायसीन जैसी एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 80 प्रतिशत बल्क ड्रग या कच्चे माल का आयात चीन से होता है। जेजियांग, गुआंगडांग, शंघाई, जियांगसू, हेबेयी, निंगशिया, हारबिन जैसे कुछ चीनी प्रांत हैं जहां से दवाओं को बनाने वाली बल्क ड्रग्स भारत आयात करता है और जब वर्ष 2019 के आखिर में चीन के वुहान प्रांत से कोरोना वायरस के संक्रमण और फिर लॉकडाउन की खबरें आनी शुरू हुई तो भारतीय फार्मा क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया था, क्योंकि बिना बल्क ड्रग्स या कच्चे माल के आयात के जेनेरिक दवाओं का उत्पादन भी संभव नहीं। गौरतलब है कि लुपिन, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, डॉ. रेड्डी और टोरेंट जैसी कंपनियां अपने एपीआइ सप्लाई के लिए चीन पर ही निर्भर हैं। भारत में प्रमुख सामग्रियों की कम उपलब्धता ने फार्मास्युटिकल सेक्टर की कमजोरी को उजागर किया है। महामारी ने इस तथ्य का पर्दाफाश कर दिया कि जरूरी मेडिकल उपकरणों के लिए भारत आयात पर निर्भर है। सप्लाई में अनियमितता की वजह से न केवल कुछ दवाओं की घरेलू कीमत आसमान पर पहुंच गई, बल्कि निर्यात पर पाबंदी की वजह से विदेशी व्यापार पर भी असर पड़ा।

एपीआइ आयात पर निर्भरता की कमी के लिए केंद्र सरकार सतर्क हुई है। भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग ने चीन से उत्पन्न हुए कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में ड्रग सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने के लिए डॉ. ईश्वर रेड्डी कमिटी का गठन किया था जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के फार्मास्युटिकल्स विभाग ने नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों को बाजार में वहनीय कीमत पर एपीआइ और अन्य फार्मूलेशन्स की पर्याप्त आर्पूति को सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया था, ताकि इस संबंध में कालाबाजारी, अवैधानिक रूप से एपीआइ को जमा करना और देश में इसकी कृत्रिम कमी को रोका जा सक एपीआइ का उत्पादन बढ़ाने को मिले प्रोत्साहन~ केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने पिछले वर्ष प्रस्तावित बल्क ड्रग्स और चिकित्सा उपकरण पार्क के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए फार्मास्युटिकल्स विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। देश भर में तीन बल्क ड्रग पार्क और चार चिकित्सा उपकरण पार्क के प्रस्तावित विकास के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए यह बैठक की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण और दवा सुरक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयात पर निर्भरता को कम करने तथा स्थानीय विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 21 मार्च, 2020 को तीन बल्क ड्रग्स पार्क और चार चिकित्सा उपकरण पार्क के विकास से संबंधित योजनाओं को मंजूरी दी थी। इस योजना को प्रोत्साहन देने के तहत भारत सरकार ने तीन बल्क ड्रग पार्क में से प्रत्येक के लिए अधिकतम एक हजार करोड़ रुपये या साझा ढांचागत संरचना सुविधाओं के निर्माण की परियोजना लागत का लगभग 70 फीसद, इनमें जो भी कम हो, एकमुश्त अनुदान के रूप में देगी।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2027-28 तक की योजना अवधि के दौरान 6,940 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश में 53 चिन्हित महत्वपूर्ण केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट और एपीआइ के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इसी प्रकार, चिकित्सा उपकरण पार्क को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार चार चिकित्सा उपकरण पार्क में से प्रत्येक के लिए अधिकतम सौ करोड़ रुपये या साझा ढांचागत संरचना सुविधाओं के निर्माण की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत , या फिर इनमें जो भी कम हो, एकमुश्त अनुदान के रूप में देगी। इसके अलावा, सरकार ने 2020-21 से 2025-26 तक 3,420 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है।

प्राचीन भारतीय संस्कृति से कोरोना को मात देने में मिलेगी बड़ी मदद

कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी ने आर्थिक रूप से जहां विश्व को बहुत पीछे धकेल दिया है, वहीं नई सामाजिक चुनौतियां भी खड़ी कर दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के स्तर पर पर भी कई समस्याएं पनपी हैं, पर इस कोरोना आपदा का एक सांस्कृतिक पक्ष भी है। कोरोना से लड़ाई वैज्ञानिक एवं मेडिकल प्रोटोकॉल के आधार पर लड़ी जा रही है, पर दूसरी ओर अलग-अलग देश अपने-अपने विशिष्ट सांस्कृतिक धरातल पर भी इससे जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में अमेरिका के मेसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पिछले साल एक परिचर्चा हुई थी कि कोरोना वायरस से निपटने में अलग-अलग देशों की प्रतिक्रियाओं में वहां की राष्ट्रीय संस्कृति कैसे अभिव्यक्त होती हैं। व्हेन कल्चर मीट्स कोविड शीर्षक वाली इस परिचर्चा की एक सीमा यह थी कि इसमें प्रमुख ध्यान इस पर था कि कोरोना से संबंधित जो प्रोटोकॉल हैं, उन्हें लेकर विभिन्न देशों के लोगों का रुख किस तरह वहां की संस्कृति से प्रभावित रहा है।

चीन में महामारी के दौरान मास्क पहनने के निर्देश का भलीभांति पालन किया गया। इसका कारण था कि तानाशाही शासन की संस्कृति में किसी तरह की छूट को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जबकि लोकतांत्रिक अमेरिका या यूरोपीय देशों में इन निर्देशों को पालन करवाना उतना आसान नहीं। इस परिचर्चा की दूसरी सीमा यह थी कि पूरी चर्चा अमेरिका या यूरोपीय देशों के अतिरिक्त पूर्वी एशियाई देश चीन, जापान, कोरिया आदि तक सीमित रही। भारत जैसे प्राचीन संस्कृति पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि भारत के सांस्कृतिक तत्वों ने कोरोना से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

देखा जाए तो अपेक्षाकृत कम विकसित और निम्न स्वास्थ्य सेवा ढांचे के बावजूद भारत में अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों के मुकाबले कोरोना मृत्यु दर कम रही। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के 20 मई, 2021 तक के आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारत के समकक्ष स्तर वाले ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र आदि में मृत्यु दर भारत से दोगुना, तीन गुना और पांच गुना तक रही। वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ा होने के बावजूद भारत में मृत्यु दर कम होने का एक बड़ा कारण यहां की विशिष्ट सांस्कृतिक जीवनशैली भी है। परंपरागत भारतीय खानपान में हल्दी, काली मिर्च, जीरा, धनिया, दालचीनी, लौंग, अजवायन, इलायची, सोंठ, मीठी नीम, पुदीना इत्यादि का घर-घर उपयोग होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत गुणकारी होते हैं। यह अनायास नहीं कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने काढ़े के उपयोग की सलाह दी थी। इसी तरह हल्दी युक्त दूध का सेवन अथवा नाक में तेल डालना जैसी परंपरागत भारतीय जीवनशैली पर भी जोर दिया गया। भारतीय संस्कृति के इन तत्वों को एलोपैथी ने भी अपने प्रोटोकॉल में स्थान दिया। दिल्ली-एनसीआर के कई बड़े हॉस्पिटल एलोपैथिक दवाइयों के अतिरिक्त कोरोना रोगी को काढ़ा भी पिलवाते हैं।

प्राचीन भारतीय संस्कृति कितनी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के अनुकूल और विभिन्न वायरसों से लड़ने में सक्षम है, इसका एक अन्य उदाहरण है यह शोधपरक आलेख कि पश्चिम के विभिन्न देशों ने 20 साल के रिसर्च के बाद पाया कि सांस छोड़ते समय हमिंग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, जो नाक में पहुंच गए कोरोना आदि वायरसों को मारता है। हमिंग करना, भारतीय योगियों द्वारा ओम मंत्र का जाप अथवा भ्रामरी प्राणायाम का ही पर्याय है। पश्चिमपरस्त सेक्युलरिस्टों की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि इस आलेख के तीन में से एक लेखक डॉ. इरमिन वान डाइकेन अमेरिकी ईसाई हैं। इसी तरह बाबा रामदेव द्वारा सुझाए गए प्राचीन भारतीय विद्या योग और प्राणायाम, खासतौर से अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका आक्सीजन स्तर को बनाए रखने में अत्यंत सहायक हैं।

कोरोना वायरस का मेडिकल साइंस में अभी कोई इलाज नहीं है। मनुष्य की अपनी प्रतिरोधक क्षमता ही फिलहाल एकमात्र इलाज है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बाबा रामदेव द्वारा प्रचारित हर गांव-नगर में पाई जाने वाली गिलोय आदि को भी लोगों ने खूब अपनाया है। इसके अतिरिक्त आंवला, अश्वगंधा आदि जड़ी-बूटियों के अलावा लगभग हर भारतीय हिंदू के घर मौजूद तुलसी अत्यंत प्रभावकारी हैं। अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इम्युनिटी बूस्टर के रूप में इनका महत्व स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि इस संदर्भ में भी शोध और वैज्ञानिक डाटा के साथ इसे प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इसे एक प्रोटोकॉल के रूप में अपनाया जा सके। इसकी आवश्यकता इसलिए और है कि भविष्य में चीन जैसे देशों से फिर जैविक आक्रमण का खतरा है। किसी नए वायरस का तत्काल इलाज न उपलब्ध होने की स्थिति में प्रतिरोधक क्षमता ही प्रमुख आरंभिक उपाय होगी। अमेरिकन जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के जनवरी, 2021 अंक में छपे एक शोध पत्र के अनुसार हल्के से मध्यम कोविड रोगियों के इलाज में इंसेंटिव स्पाइरोमीटर उपयोगी है, जो एक तरफ फेफड़ों को मजबूत करता है और दूसरी तरफ म्यूकस निर्माण रोकता है। इससे निमोनिया होने की संभावना कम होती है। इंसेंटिव स्पाइरोमीटर गहरी सांस लेकर जोर से फूंकने का अभ्यास करने वाला यंत्र है। भारतीय संस्कृति में शंख बजाने की जो परंपरा है, वह इसी तरह की चीज है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के 70 साल बाद भी हम अपनी अधिकांश ज्ञान-परंपरा और गौरवशाली वैज्ञानिक संस्कृति से अनभिज्ञ हैं।

वैक्सीनेशन पर दूर हुई उलझन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीके लगवाने का इंतजाम करेगी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उबरने की प्रक्रिया में है, लेकिन खतरा टला नहीं है। दूसरी लहर के उतार के बीच जो थोड़ा-बहुत समय हमें मिला है, उसका सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर देश को यह बताया है कि वह सरकार की टीका नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। काफी समय से यह मांग की जा रही थी कि पल्स पोलियो मुहिम समेत अब तक के तमाम टीकाकरण अभियानों की तरह कोरोना का टीका भी सबको मुफ्त लगाया जाना चाहिए। यह लोगों को सरकार की ओर से किसी तरह की सुविधा या सामान मुफ्त देने की बात नहीं थी। यह उनका जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षित करने का मामला था, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो भी सबको सुरक्षित किए बगैर देश की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

साफ है कि यह फैसला महामारी के खिलाफ जंग में मील का पत्थर साबित हो सकता है। टीका खरीदने की कथित लिबरलाइज्ड पॉलिसी से जो गफलत पैदा हुई थी, ताजा घोषणा से वह भी दूर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पॉलिसी की तीखी आलोचना की थी। अलग-अलग कीमतों से भ्रम और असमंजस तो पैदा हो ही रहा था, राज्यों पर अलग से टीके खरीदने की जिम्मेदारी डालने से परस्पर दोषारोपण की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो गई थी। राज्य शिकायत कर रहे थे कि उन्हें कंपनियां जरूरत से काफी कम टीका दे रही हैं। इस बीच, राज्यों ने टीका खरीदने के लिए जो ग्लोबल टेंडर दिए, उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला।

इसलिए एनबीटी ने भी अपने संपादकीय में केंद्र से राज्यों की ओर से टीका खरीदने की अपील की थी। अब जब केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राज्यों के हिस्से की ओर से भी वही वैक्सीन खरीदेगी तो किसी संदेह या असमंजस की गुंजाइश नहीं रही।

इसी मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने की घोषणा भी महत्वपूर्ण है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी बड़े पैमाने पर उद्योग-धंधों और रोजगार पर बुरा असर हुआ। ऐसे में इस पहल से देश की 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर देखें तो सोमवार को हुई घोषणा सरकार की नीतियों में ऐसा संशोधन है, जो महामारी के खिलाफ हमारी मोर्चेबंदी को मजबूत करेगा।

डब्ल्यूएचओ को सुरक्षा परिषद और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी शक्तियां प्रदान करना समय की मांग

> तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विश्व व्यवस्था से अमेरिका के पीछे हटने, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की बीआरआइ यानी बेल्ट एंड रोड एनिशियेटिव के इर्दगिर्द नए वैश्विक आर्थिक ढांचे के अलावा इमैनुअल मैक्रों और जस्टिन ट्रूडो की वर्तमान उदारवादी व्यवस्था पर दोहरे वार की दुहाई जैसी अवधारणाएं प्रमुख रहीं। बहरहाल फिलहाल जो वैश्विक घटनाक्रम आकार ले रहा है, उसमें मौजूदा नेतृत्व का ध्यान कहां केंद्रित दिखता है? हमें राष्ट्र-राज्य प्रभुत्व का निर्माण और उसके सशक्तीकरण के साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन का संरक्षण भी संबद्ध करना होगा। मौजूदा महामारी के प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि भविष्य में दस्तक देने वाली महामारियां और तबाही ला सकती हैं।

वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को साकार रूप देने के लिए जब अंतरराष्ट्रीय राजनयिक बिरादरी जुटी तो एक वैश्विक स्वास्थ्य संस्था के गठन का विचार भी उनके विमर्श के केंद्र में था। इस प्रकार 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ अस्तित्व में आया। महामारी नियंत्रण, क्वारंटाइन उपाय और दवा मानकीकरण जैसे विशिष्ट कार्य उसे पूर्ववर्ती लीग ऑफ नेशंस से विरासत में मिले। पेरिस स्थित इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ पब्लिक हेल्थ का भी डब्ल्यूएचओ में ही विलय हो गया। तबसे अब तक वैश्विक परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अध्याय सात के अनुप्रयोगों का तत्काल विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। उनके अभाव में डब्ल्यूएचओ एक निष्प्रभावी संस्थान बना रहेगा। समय की मांग है कि डब्ल्यूएचओ को सुरक्षा परिषद और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ जैसी शक्तियां प्रदान की जाएं। ऐसा न किए जाने से डब्ल्यूएचओ अपने समक्ष उत्पन्न गंभीर चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं हो सकेगा। इस बात से बिल्कुल इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 जैसी महामारी से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जैसे जोखिम उत्पन्न हुए हैं, वे किसी भी मामले में मनी लांड्रिंग या आतंक को वित्तीय मदद पहुंचाने जैसे खतरों से जरा भी कम नहीं हैं। इसके बावजूद डब्ल्यूएचओ के कोई विशिष्ट सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य मानक नहीं हैं, जो सभी देशों पर एकसमान रूप से लागू होते हों। विशेषकर महामारी के नियंत्रण से लेकर लापरवाही बरतने वाले उन देशों की जवाबदेही तय कर पाने को लेकर कोई प्रविधान

नहीं, जो देश महामारी से जुड़ी सूचनाओं की स्वतंत्र समीक्षा के लिए उन्हें साझा करने से कतराते हों।

डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करती है। कोविड-19 महामारी से निपटने में अपनी भूमिका को लेकर यह संस्था चर्चा के केंद्र में रही है। महामारी फैलने के बाद इस वायरस के उद्गम स्थल को लेकर भी अंदरखाने एक बहस शुरू हो गई है। पहली बार कोरोना वायरस के पकड़ में आने और विश्व को समय से उसकी सूचना देने और उससे निपटने के लिए पर्याप्त प्रयासों जैसे बिंदु भी र्चिचत रहे। मई 2020 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डब्ल्यूएचओ से कहा था कि वह वायरस के स्नोत और उसके मानवीय आबादी में प्रसार की पड़ताल करे। इसके बाद डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों ने इस साल 14 जनवरी से 10 फरवरी के बीच चीन के उस वुहान शहर का दौरा किया, जहां से कोरोना वायरस फैला था। फिर 30 मार्च, 2021 को डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की, जिसकी अमेरिका और जापान जैसे 14 देशों के समूह ने आलोचना की। उन्होंने इस रिपोर्ट को अपूर्ण और बहुत देर से जारी की गई, करार दिया, जिसमें पर्याप्त तथ्यों का अभाव रहा। इस पर डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने यही कहा कि यह निष्कर्ष अपर्याप्त है।

हालांकि टीम का मानना है कि प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने की परिकल्पना के पुष्ट होने के आसार बहुत कम हैं, जिसकी आगे और जांच की दरकार है। संयुक्त राष्ट्र तंत्र और डब्ल्यूएचओ को एफएटीएफ के अनुभव से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उसे जनस्वास्थ्य को लेकर व्यापक नियमों के मानक बनाने होंगे। भविष्य में संभावित महामारियों के प्रबंधन और उनसे निपटने में सदस्य देशों की अपेक्षाओं और इन मानकों के अनुपालन में इन देशों के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुपालन न करने की स्थिति में प्रतिबंधों का प्रविधान करना होगा। मामले की गंभीरता को लेकर जागरूकता का प्रसार और भविष्य में संभावित महामारियों के जोखिमों को घटाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। इस ढांचे में सदस्य देशों का दायित्व भी स्पष्ट रूप से रेखांकित होना चाहिए, जो स्वतंत्र जांच-पड़ताल के लिए संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े उपलब्ध कराएं, बिल्कुल वैसे जैसे आइएमएफ, संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ प्रणाली में होता है। साथ ही इस मामले में सहयोग नहीं करने के परिणाम भुगतने का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। इसमें एफएटीएफ तंत्र से प्रविधान लिए जा सकता हैं। इन प्रविधानों में दंडात्मक शुल्क, आवाजाही प्रतिबंध और अन्य आर्थिक प्रतिबंध शामिल होने चाहिए। यदि इसे अमल में लाया जाता है तो इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अंतरराष्ट्रीय समन्वय एवं पर्यवेक्षण प्रणाली के लिए राह खुलेगी। डब्ल्यूएचओ संविधान का अनुच्छेद एक सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर के लक्ष्य को परिभाषित करता है। वहीं अनुच्छेद दो संगठन के कार्यों पर प्रकाश डालता है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतरराष्ट्रीय मानकों और महामारी से निपटने के लिए कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में इस संविधान की समीक्षा आवश्यक हो गई है।

बदली हुई परिस्थितियों में डब्ल्यूएचओ के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल करने के लिए कुछ संशोधन आवश्यक हों तो वे किए जाएं। वर्ष 2017 में दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यूईएफ के मंच पर भविष्य के संभावित वैश्विक ढांचे से जुड़ी तीन अवधारणाएं पेश की गईं।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विश्व व्यवस्था से अमेरिका के पीछे हटने, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की बीआरआइ यानी बेल्ट एंड रोड एनिशियेटिव के इर्दगिर्द नए वैश्विक आर्थिक ढांचे के अलावा इमैनुअल मैक्रों और जस्टिन ट्रूडो की वर्तमान उदारवादी व्यवस्था पर दोहरे वार की दुहाई जैसी अवधारणाएं प्रमुख रहीं। बहरहाल फिलहाल जो वैश्विक घटनाक्रम आकार ले रहा है, उसमें मौजूदा नेतृत्व का ध्यान कहां केंद्रित दिखता है? हमें राष्ट्र-राज्य प्रभुत्व का निर्माण और उसके सशक्तीकरण के साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन का संरक्षण भी संबद्ध करना होगा। मौजूदा महामारी के प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि भविष्य में दस्तक देने वाली महामारियां और तबाही ला सकती हैं। यहां तक कि कम प्रभावित क्षेत्रों को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कारगर वैश्विक ढांचे और सहयोग-समन्वय में ही समझदारी निहित है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा- भाजपा ने पारदर्शिता से दिया युवाओं को रोजगार

देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया है। नौकरियों की बंदरबांट नहीं की। अभी तक सरकारी, गैर सरकारी, स्थायी व अस्थायी रूप से सात लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है। सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर सरकारी एवं गैर सरकारी पदों पर भर्तियां करने जा रही है।

गुरुवार को एक बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लगभग डेढ़ साल से कोरोना के कारण हर तरह की सरकारी, गैर सरकारी और व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। बावजूद इसके प्रदेश में किसी भी संविदा अथवा आउटसोर्स कार्मिक की सेवा को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि सरकार उनके लिए रोजगार सृजन की नई योजनाएं लेकर आई है। कांग्रेस के रोजगार संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार में नौकरियों की बंदरबांट के आरोप लगे थे। तब चहेतों को रेवड़ियों की तरह सरकारी नौकरी बांटने और पिछले दरवाजे से हुई नियुक्तियों को लेकर जम कर हंगामा हुआ था। कांग्रेस शासनकाल में बेरोजगारों के साथ केवल छलावा हुआ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार पूर्ण पारदर्शिता से सबका साथ, सबका विकास की भावना से कार्य कर रही है। भाजपा ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का एतिहासिक कार्य किया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रोजगार के वर्ष 2017 से 2020 तक के वर्षवार आंकड़े देते हुए कहा कि इस अवधि में सरकार ने 712837 रोजगार सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार कोरोना से आम लोगों की रक्षा के लिए लड़ रही है। विपक्ष को भी आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़कर सेवा कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और रोजगार की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है।

झारखंड में यास तूफान के 15 दिनों बाद भी 14 जिलों ने नहीं दी नुकसान की रिपोर्ट

रांची । चक्रवाती तूफान यास से राज्य में कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन 15 दिनों के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। सिर्फ दस जिलों ने ही अपनी रिपोर्ट आपदा प्रबंधन प्रभाग को भेजी है। अब भी 14 जिले ऐसे हैं, जहां से नुकसान की आकलन संबंधित रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट नहीं देने वाले सभी 14 जिलों को आपदा प्रबंधन प्रभाग रिमाइंडर भेजने जा रहा है ताकि नुकसान संबंधित रिपोर्ट मिल सके। रिपोर्ट मिलने के बाद ही उसके आधार पर आपदा राहत कोष से संबंधित जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार को जिन जिलों ने यास तूफान से नुकसान संबंधित रिपोर्ट दी है, उनमें हजारीबाग, गढ़वा, कोडरमा, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा, बोकारो, पाकुड़, धनबाद व खूंटी जिले शामिल हैं। शेष जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि यास तूफान से राज्य में कितने का नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि यास तूफान से राज्य में करीब पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से झारखंड को केवल 227 करोड़ रुपये ही मिले थे। गौरतलब है कि यास तूफान के दौरान ही बुंडू-सोनाहातू के बीच करोड़ों की लागत से निर्मित पुल ढह गया था। इसके अलावा कई जिलों में बिजली के खंभे गिरने, कच्चा मकान ध्वस्त होने, सड़क पर पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आईं। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान की आशंका है। यहां हरी सब्जियों के फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

रायपुर रेलवे स्टेशन में मिली अज्ञात लाश की पीएम रिपोर्ट में हत्या का राजफाश

रायपुर । राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के परिसर में मिली अज्ञात लाश की पीएम रिपोर्ट आने के बाद जीआरपी थाना प्रभारी आरके बोरझा ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए निरीक्षक आरके बोरझा ने बताया कि मामला पांच जून की दोपहर का है, जब सूचना मिली थी कि ओला टैक्सी पार्किंग परिसर के पास पेड़ पौधे जंगलनुमा जैसी जगह पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि शव डिस्पोज हालत में था और चार से पांच दिन पुराना लग रहा था। इसके बाद तत्काल मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए शव को आंबेडकर अस्पताल रवाना किया गया। अब डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हत्या का कारण धारदार नुकीले हथियार से सीने में वार सहित शरीर में कई जगहों पर चोट बताया गया है। इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपित की तलाश की जा रही है। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, डॉक्टर ने बताया कि मृतक की उम्र 40 से 45 वर्ष के करीब है। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि पुलिस आखिर कातिल की तलाश कैसे कर पाएगी क्योंकि अभी तक मृतक कौन है, इसके बारे में ही जानकारी नहीं मिल पाई है। उधर, पुलिस लापता लोगों की दर्ज की गई शिकायत में बताए गए हुलिए के आधार पर मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पटना में कार पर प्रेस का स्टिकर लगा कर रहे थे शराब तस्करी, पांच डिलीवरी ब्वॉय गिरफ्तार

पटना । दीघा थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह-सुबह शराब की तस्करी में लगे पांच डिलीवरी ब्वॉय को गिरफ्तार किया है। आरोपित दो क्रेटा कार से शराब की खेप लेकर हाजीपुर से पटना आ रहे थे। किसी को उनपर शक ना हो इसके लिए उन्होंने कार पर प्रेस का स्टिकर लगा रखा था। कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पुलिस शराब जब्त कर गिरफ्तार आरोपितों से शराब तस्करी के संबंध में पूछताछ कर रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर कार से शराब की खेप लेकर हाजीपुर से पटना आ रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही दीघा थाना पुलिस की टीम ने जेपी सेतु पर नाकेबंदी कर दी। इसी दौरान पुलिस को हाजीपुर से पटना की तरफ आ रही दो संदिग्ध क्रेटा कार दिखी। पुलिस ने कार रुकवा तलाश ली तो पता लगा चला कि उनमें उनमें भारी मात्रा में शराब भरी हुई है। जिसके बाद कार में सवार पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपित डिलीवरी ब्वॉय हैं। वे शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे थे। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि पुलिस को शराब तस्करी का शक ना हो इसके लिए उन्होंने कार पर प्रेस का स्टिकर लगा रखा था। मालूम हो कि अनलॉक होते ही पटना में शराब तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। गत दिनों भी बुद्धा कालोनी और दीघा थाना पुलिस शराब तस्करी के अलग-अलग मामले में कई तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है।

पंजाब में कोरोना से मौत के आंकडों में गड़बड़ी, प्रोटोकाल से अंतिम संस्कार व सरकारी मृतक संख्या में भारी अंतर

लुधियाना/जालंधर । बिहार में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद पंजाब में भी इसकी संभावना जताई जा रही है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पंजाब में भी कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। यह आशंका इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कोरोना प्रोटोकाल से अंतिम संस्कार और मौत के सरकारी आंकड़ों में लगभग 50 फीसद का अंतर आ रहा है। जालंधर के श्मशानघाटों में एक मई से 10 जून तक 635 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकाल से किया गया, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन 41 दिनों में सिर्फ 340 लोगों की ही कोरोना से मौत हुई। इनमें से 550 अंतिम संस्कार तो सिर्फ मई में ही हुए, जबकि प्रशासन के रिकार्ड में सिर्फ 288 मौतें ही दर्ज हैं। जून में भी अब तक 85 लोगों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाल से किया गया है, जबकि सरकारी रिकार्ड में सिर्फ 52 मौतें दर्ज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 295 मौतें कोरोना से नहीं हुई, तो इनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकाल से क्यों किया गया। इसी तरह लुधियाना में विभाग के अनुसार मई में कोरोना के कारण 624 और जून में 54 लोगों की मौत हुई है। वहीं, श्मशानघाटों पर मई में 1116 और जून 113 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकाल के तहत किया गया। सेहत विभाग इसके पीछे सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला देता है, लेकिन मरने वालों के पारिवारिक सदस्य असमंजस में हैं कि क्या उनके किसी अपने को कोरोना था क्या उनकी मौत कोरोना से हुई थी अगर नहीं तो उन्हें अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं होने दिया गया।

श्री पारस हास्पिटल में 24 घंटे में हुई थी एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत, वीडियो बनाने वाले तक पहुंची पुलिस

आगरा । क्या बताऊं, जो मेरे ऊपर बीता है। चौबीस घंटे के भीतर श्री पारस हास्पिटल में पहले पिता जी को खोया फिर भाई की पत्नी की मौत हो गई। दो लोगों की मौत ने परिवार को हिलाकर रख दिया। यह दोनों मौतें 26 अप्रैल को बिना आक्सीजन की कमी से हुई है। दोनों के इलाज में हद दर्जे की लापरवाही बरती गई है। मौत के मॉकड्रिल के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यह शब्द हैं कृष्णा कालोनी जीवनी मंडी रोड निवासी अशोक चावला के। अशोक चावला ने डीएम से शिकायत की है। उधर, शनिवार को प्रशासन को एक और शिकायत डाक से प्राप्त हुई है। शिकायतों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। उल्लेखनीय है कि आक्सीजन की कमी से यहां 22 मरीजों की मौत होने की चर्चा है, जो आक्सीजन की कमी को लेकर माकड्रिल में होना बताया जा रहा है।

अशोक ने बताया कि चार अप्रैल को पिता वासुदेव को कोविड की पुष्टि हुई थी। 12 अप्रैल की रात में पिता जी की तबीयत तेजी से खराब होने लगी। जिस पर श्री पारस हास्पिटल में भर्ती कराया। 20 अप्रैल को वेंटिलेटर पर रखने की बात कही गई। 26 अप्रैल को डाक्टर ने बुलाकर कहा कि आक्सीजन की कमी हो गई है। खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। इस पर आक्सीजन के इंतजाम में जुट गए और सिलेंडर मंगा भी लिए लेकिन बीस मिनट बाद हास्पिटल प्रशासन ने बताया कि वासुदेव की मौत हो गई है। 27 अप्रैल को छोटे भाई अमित की पत्नी मनीषा चावला की भी मौत हो गई। डेथ सर्टिफिकेट तो जारी हुए लेकिन मृतकों की सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।

हास्पिटल प्रशासन है भाभी मीना की मौत का जिम्मेदार- मालवीय कुंज निवासी गरिमा का कहना है कि भाभी मीना को 21 अप्रैल को कोविड की पुष्टि हुई थी। श्री पारस हास्पिटल में भर्ती कराया गया। 26 अप्रैल को मौत हो गई, भाभी की मौत आक्सीजन की कमी से हुई है। इसका जिम्मेदार हास्पिटल प्रशासन है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

कोरोना का भय दिखाकर वसूला पैसा- भरथना इटावा निवासी राजू सिंह का कहना है कि बहनोई रिंकू यादव को कोविड नहीं था लेकिन जांच के नाम पर श्री पारस हास्पिटल प्रशासन ने परेशान किया। कोरोना पाजिटिव मानकर इलाज किया गया। आक्सीजन के नाम पर वसूली की गई। इलाज में लापरवाही बरतने से 26 अप्रैल को रिंकू की मौत हो गई।

डाक्टर को मिलनी चाहिए सजा ए मौत- सौरभ अग्रवाल का कहना है कि पत्नी राधिका अग्रवाल का निधन 26 अप्रैल को श्री पारस हास्पिटल में हुआ है। आक्सीजन कमी और इलाज में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है। उस आधार पर डाक्टर को सजा ए मौत मिलनी चाहिए।

छिन गया जीवनसाथी- आगरा निवासी अशोक कुमार का कहा है कि श्री पारस हास्पिटल प्रशासन की गलती का खामियाजा जिंदगी भर उन्हें उठाना पड़ेगा। 26 अप्रैल को पत्नी मुन्नी देवी की मौत हो गई। जीवनसाथी का साथ हास्पिटल प्रशासन ने छीन लिया।

कुल दस शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें तीन रीप्रजेंटेशन फार्म के रूप में हैं। कुछ शिकायतें डाक से और भी प्राप्त हो सकती हैं। सभी शिकायतों की जांच होगी। वीडियो बनाने और उसे जारी करने वाले व्यक्तियों तक टीम पहुंच चुकी है। मामले की पूरी जांच की जा रही है।- **प्रभु एन सिंह, डीएम आगरा**

प्रतापगढ़ में पुलिस ने ढहा दिया कोरोना माई का मंदिर, गांव के लोग करने लगे थे पूजा

प्रतापगढ़ । विवाह के लिए जयपाल के बाद स्टेज पर चढने् से पहले दुल्हन के रिवाल्वर से फायरिंग का मामला अभी पुराना भी नहीं पड़ा था कि प्रतापढ़ में लोगों ने मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर कोरोना माई की पूजा भी शुरू कर दी। मामले के तूल पकडने् जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने शुक्रवार देर रात कोरोना माई के मंदिर को ढहा दिया। प्रतापगढ़ जिले में सांगीपुर बाजार से दो किलोमीटर दूर दीवानगंज रोड पर जूही शुकुलपुर गांव में बने कोरोना माई मंदिर को पुलिस ने शुक्रवार रात ढहा दिया। सांगीपुर पुलिस देर रात यहां पहुंची थी। इसके बाद तोड़ी गई मूर्ति का अवशेष ट्रैक्टर ट्राली में रखकर बाहर कर दिया। मंदिर में मूर्ति स्थापना कराने वाले लोकेश श्रीवास्तव के बड़े भाई नागेश कुमार श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया गया है। अब परिवार वाले पुलिस पर दबंगई का आरोप लगा रहे हैं।

प्रतापगढ़ का यह मंदिर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ तो भीड़ बढने् लगी। यहां पर सात जून को गांव की ही दीपमाला श्रीवास्तव ने नीम के पेड़ तले मंदिर की स्थापना कराई थी। सांगीपुर थाना इलाके के जूही शुकुलपुर में चार दिन पहले कुछ लोगों ने कोरोना माता का मंदिर बनवाया था। जहां लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए पूजा अर्चना करने लगे थे। मंदिर में कोरोना देवी की छवि को प्रतिमा के रूप में साकार किया गया था। इसके बाद यहां पूजा-पाठ शुरू हो गया था। ग्रामीणों के अनुसार यहां कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग पॉजिटिव हो गए थे। इलाज के बाद वो सभी ठीक हो गए थे। ऐसे में ग्रामीणों ने पूजा-पाठ का सहारा लिया। लोगों ने गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे कोरोना माता की मूर्ति स्थापित की और सुबह-शाम आरती करने लगे थे।

रामनगरी अयोध्या में शिलाओं से निर्मित छह प्रवेश द्वार करेंगे आने वालों का स्वागत

अयोध्या । पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों बीते वर्ष पांच अगस्त को नींव का पत्थर रखे जाने के बाद से रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी रूपरेखा ऐसी तैयार की गई है कि यहां पर आने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। अयोध्या में छह जिलों से प्रवेश करने वाले लोग प्रवेश द्वारों पर पहुंचते ही लोग बेहद आनंद की अनूभूति करेंगे। माना जा रहा है कि यह प्रवेश द्वार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही रामनगरी को नई पहचान देंगे।

अथर्व वेद में वर्णित नौ द्वार वाली अयोध्या के स्वरूप को रामनगरी के पुनर्निमाण में भी प्रमुखता से स्थान देने की कोशिश चल रही है। अभी नौ द्वारों में छह द्वारों के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रामनगरी के पुनर्निमाण को लेकर संतों की राय पर इसे साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट में इस परिकल्पना को स्थान मिला है।

इसके लिए रामनगरी को प्रयागराज, गोंडा, वाराणसी, लखनऊ, रायबरेली व गोरखपुर से जोडने् वाले मार्गों पर इन द्वारों का निर्माण प्रस्तावित है। इन प्रवेश द्वार की डिजाइन सिक्स लेन, फोर लेन तथा टू लेन सड़कों को ध्यान में रखकर की जा रही है। एक प्रवेश द्वार की अनुमानित लागत दस से 15 करोड़ रुपया आने की संभावना है।

विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल ड्क्षसह की देखरेख में ग्लोबल कंसल्टेंट एजेंसी ली एसोसिएट्स ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। प्रवेश द्वारों की प्रारंभिक डिजाइन तैयार कर गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की गई थी। इस डिजाइन को अभी फाइनल नहीं किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट से जुड़े जानकारों की माने तो अभी छह द्वारों का निर्माण करने की योजना है। तीन और द्वारों के निर्माण की गुंजाइश तलाशी जा रही है। निकट भविष्य में इन तीन द्वारों का निर्माण भी कराने का प्रयास होगा। धर्मनगरी में बनने वाले प्रवेश द्वार भी भगवान राम और उनके सेवक तथा सहयोगियों के नाम पर होंगे।

प्रवेश द्वारों की डिजाइन सिक्स लेन, फोर लेन और टू लेन मार्गों को ध्यान में रख कर तैयार की जा रही है। ये द्वार शिलाओं से निर्मित होंगे। इन शिलाओं की खासियत राममंदिर में प्रयुक्त होने वाले पत्थरों की तरह होगी। एक प्रवेश द्वार की अनुमानित लागत दस से 15 करोड़ रुपये है। प्रवेश द्वार के पास ही सुव्यवस्थित धर्मशालाएं भी बनाई जाएंगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल ड्क्षसह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप रामनगरी को आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किए जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी क्रम में रामनगरी की सीमा पर छह भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण प्रस्तावित है। इनकी डिजाइन तैयार कराई जा रही है।

प्रदेश के सात जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं, 24 घंटे में 619 नए केस

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार का व्यापक पैमाने पर चल रहे अभियान का बड़ा असर हो रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को जो सैंपल की रिपोर्ट आई है, उसमें सात जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी नया संक्रमित केस नहीं मिला है। अपर मुख्य सचिव सूचना डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे की जो सैंपल टेस्ट रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार आज कोरोना वायरस संक्रमण के 619 नए कोविड मामले मिले हैं। प्रदेश के 75 जिलों में से सात जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला जबकि 45 जिलों में सिंगिल डिजिट के अंक में नए संक्रमित मिले हैं। 23 जिलों में दस से पचास तक नए केस मिले हैं। अब प्रदेश में कुल सक्रिय केस की संख्या 11,127 रह गई है। प्रदेश में आज 1642 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ट्रैक, टेस्ट तथा ट्रीट की नीति पर सरकार के लगातार काम करने के कारण ही प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार काफी नियंत्रित है। बीते 24 घंटे में 74 लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें कानपुर में 15, गोरखपुर में छह तथा बरेली में पांच लोग हैं। लखनऊ में सर्वाधिक 49 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि वाराणसी में इनकी संख्या 24 की है।

डॉ. सहगल ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण का काम भी काफी गति पकड़ चुका है। सरकार 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का एक साथ टीकाकरण करा रही है। तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारी तेज- प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की थर्ड स्ट्रेन को भी लेकर बेहद गंभीर है। माना जा रहा है कि इसका सर्वाधिक असर बच्चों पर होगा। प्रदेश सरकार इसी क्रम में 600 बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स भर्ती कर रही है।

ओमप्रकाश राजभर ने भाजपा से गठबंधन की अटकलों को किया खारिज, कहा- डूबती नैया में नहीं करेंगे सवारी

लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना को खारिज करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा डूबती नैया है, उस पर सवार न होंगे। उन्होंने प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अलावा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे वादों के साथ चुनाव में उतरा जाएगा।

पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार में बदलाव की चर्चाओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनसमस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने में लगी मंडली का ड्रामा दो-तीन दिन में खत्म हो जाएगा। शुक्रवार को भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक में भाग लेने के बाद राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किए जाने पर भी सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो भाजपा को पिछड़ों की याद आ जाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाना हो तो बाहर से लाकर बना देते हैं। चार साल से अधिक बीत गए, परंतु एक भी काम पूरा नहीं हुआ। पिछड़ों को हिस्सा नहीं देने वाली भाजपा किस मुंह से पिछड़ों से वोट मांगने जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भाजपा को हराएगा उसका साथ दिया जाएगा। भाजपा को भारतीय झूठ पार्टी करार देते हुए पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, तो सरकार की 2022 में विदाई तय है। राजभर ने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के साथ चुनावी चर्चा की। चर्चा के बाद राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की चुनावी तैयारियों के बारे में बताया।

कानपुर के बिल्हौर में विकास दुबे की पत्नी रिचा ने पुलिस की मदद से लिया खेतों पर कब्जा

कानपुर । उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब उसकी पत्नी रिचा दुबे विरासत को सहेजने में जुट गई है। रिचा दुबे ने शुक्रवार को बिल्हौर के सकरवां गांव में कुख्यात विकास दुबे की दस बीघा जमीन पर पुलिस की मदद से कब्जा प्राप्त किया। विकास दुबे की की मौत के बाद गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस मामले की जांच के बाद तहसीलदार ने विवादित जमीनों पर विकास दुबे का ही मालिकाना हक बताया। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को सकरवां पहुंची विकास दुबे की पत्नी रिचा ने नदीहा चौकी पुलिस की मौजूदगी में जमीनों पर कब्जा लिया।

तहसील के सकरंवा गांव में बिकरू निवासी कुख्यात विकास दुबे ने फरवरी-2016 को उन्नाव के शशिकांत से 24 बीघा जमीन का बैनामा कराया था। खतौनी में भी विकास दुबे का नाम दर्ज हो गया था। दो जुलाई की रात बिकरू गांव में दबिश के दौरान बिल्हौर सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में एसटीएफ ने विकास दुबे और उसके छह गुर्गों को मार गिराया था।

विकास के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद गांव के ही तीन लोगों ने उसकी दस बीघा जमीन पर अपना दावा जताते हुए कब्जा कर लिया था। इसके बाद गांव के एक व्यक्ति ने एसडीएम से कब्जे की शिकायत की थी। तत्कालीन एसडीएम पीएन सिंह के निर्देश पर तहसीलदार ने जांच की थी। इस जांच प्रक्रिया में उक्त जमीनों पर विकास दुबे का ही मालिकाना हक मानते हुए कब्जेदारों को बेदखल कर दिया गया था, लेकिन वह लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। इस मामले मे विकास दुबे की पत्नी रिचा ने मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र देकर जमीनों पर कब्जा दिलाने की मांग की थी।

ककवन थाना प्रभारी के निर्देश पर शुक्रवार को नदीहा पुलिस चौकी इंचार्ज ने सकरवां में विवादित दस बीघा जमीन पर रिचा को कब्जा दिलाया। ककवन थाना प्रभारी संतोष कुमार ओझा ने बताया अधिकारियों के निर्देश पर रिचा दुबे को कब्जा दिला दिया गया है।

ग्राम प्रधान समेत तीन के खिलाफ मुकदमा करने की मांग- रिचा दुबे ने पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर सकरवां के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुशील दुबे व श्रीकांत दीक्षित समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इनके खिलाफ जमीन पर कब्जे की नीयत से बटाईदार को धमकाने का आरोप लगाया है।

बीपीएससी में सफल निकिता के पास डिग्री न होने से पात्रता रद, मगध यूनिवर्सिटी की कारगुजारी से मेधावी बेटी मुसीबतों में फंसी

बोधगया/नालंदा । मगध विश्वविद्यालय की कारगुजारी का खामियाजा एक मेधावी बेटी को भुगतना पड़ा। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 64वीं परीक्षा में सफल बिहाशरीफ की निकिता की पात्रता रद कर दी गई, क्योंकि वर्ष 2013 में बीएससी परीक्षा पास करने की मगध विश्वविद्यालय से उसे डिग्री नहीं मिली।

निकिता के सिर से मां-पिता का साया उठ गया था। पढने् की ललक थी, तो बड़ी बहन की ससुराल में रहकर पढ़ाई की। अपनी मेधा की बदौलत बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। लगा कि मेहनत सफल हो गई, लेकिन अब उसके पास सिस्टम को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा है।

नौकरी के लिए लड़नी होगी लंबी लड़ाई- बता दें कि मगध विश्वविद्यालय डिग्री को लेकर हमेशा से चर्चा में रहा है। कई कुलपति आए, कई तरीके अपनाए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बिहारशरीफ के खंदकपर निवासी पवन कुमार सिन्हा की बेटी निकिता ने नालंदा कालेज, बिहारशरीफ से बीएससी की परीक्षा 2013 में पास की थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के सात वर्ष बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिग्री मुहैया नहीं कराई। नतीजतन, आयोग ने उसे दो दिन पहले पत्र भेज दिया, जिसमें लिखा था कि स्नातक का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण आपका परिणाम रद किया जाता है। अब निकिता को नौकरी प्राप्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई लडऩी पड़ेगी और इंतजार भी करना पड़ेगा।

लॉकडाउन का बहाना- मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डा. भृगुनाथ कहते हैं कि छात्रा को डिग्री मुहैया करा दी गई है। कोविड-19 के कारण लाकडाउन में विश्वविद्यालय बंद था। निकिता के डिग्री के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को भी सूचना मेल के माध्यम से दी गई थी।

पिछले नौ माह से विश्वविद्यालय के चक्कर काट रही थी निकिता

निकिता ने बताया कि वह अपने प्रमाण पत्र के लिए पिछले नौ माह से विश्वविद्यालय के चक्कर काट रही थी। जब बीपीएससी की लिखित परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार का समय आया, तो वह अपना प्रमाण पत्र लाने फिर से बोधगया गई। वहां साक्षात्कार का पत्र मांगा गया।

उस आधार पर टेस्टीमोनियल लिखकर दे दिया गया और उसने साक्षात्कार दे दिया। उसके बाद भी विश्वविद्यालय का चक्कर काटती रहीं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक सप्ताह पहले हंगामा किया तो रजिस्ट्रार ने आयोग को मेल कर यह बताया दिया कि उसके प्रमाण पत्र जमा करने की देरी के पीछे विश्वविद्यालय की प्रक्रिया है। इसलिए निकिता को मौका दिया जाए। निकिता सिन्हा ने सवाल उठाया कि अगर दिक्कत थी तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार लेने वक्त बीपीएससी के अफसरों ने क्यों नहीं पूछा। विश्वविद्यालय का टेस्टीमोनियल भी आयोग नहीं मानता!

जानलेवा हमले के मामले में पूर्व बसपा एमएलसी संजीव द्विवेदी उर्फ रामू द्विवेदी लखनऊ से गिरफ्तार

लखनऊ । शराब व्यापारी संजय केडिया पर जानलेवा हमले के पुराने मामले गोरखपुर में दर्ज एक केस के मामले में पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी से विधान परिषद सदस्य रहे संजीव द्विवेदी उर्फ रामू द्विवेदी को बहुखंडी आवास के पास से गिरफ्तार किया। लखनऊ में उसे देवरिया पुलिस ने धेनुमती अपार्टमेंट, बालू अड्डे के पास से पकड़ा है।

धमकी देने के इस मामले में पुलिस फिर से जांच कर रही है। रामू द्विवेदी के खिलाफ गोरखपुर सदर कोतवाली में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले की विवेचना कुशीनगर पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई। पुलिस ने प्राणघातक हमला होने का अपराध नहीं पाए जाने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस दौरान युवा समाजसेवी व्यापारी निकुंज अग्रवाल की पिटाई कर धमकी देने के मामले में भी सुलह हो गई थी। देवरिया की पुलिस इन दोनों मामलों की फाइल फिर से खंगाली रही थी। कारोबारी संजय केडिया और निकुंज अग्रवाल से पुलिस ने नई तहरीर देकर पूर्व एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू की। एडीजी जोन अखिल कुमार ने एसपी को पत्र भेज कर रामू द्विवेदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे उनसे जुड़े लोग और संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। शुक्रवार को एसपी डॉ. श्रीपति मिश्र ने खुद कोतवाली में पूर्व एमएलसी पर दर्ज मामलों के बारे में जानकारी ली थी।

देवरिया कोतवाली से छह सदस्यीय पुलिस टीम ने लखनऊ की हजरतगंज पुलिस से संपर्क किया था। इसके बाद देवरिया पुलिस ने शुक्रवार देर रात हजरतगंज पुलिस के साथ छापेमारी की थी।

जन्मदिन के बहाने बिहार की राजनीति में छाए रहे लालू, सीएम नीतीश व कुशवाहा-मांझी की बधाई के मायने सुर्खियों में

पटना । अपने 74 वें जन्मदिन के मौके पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली में हैं। वहां आधी रात में जन्मदिन का केक भी कटा, मगर शरीर से गैर-हाजिर रहने के बावजूद लालू शुक्रवार को दिन भर पटना के राजनीतिक गलियारे में छाये रहे। समर्थकों के दिल पर, तो विरोधियों के दिमाग पर उनके जन्मदिन का असर पड़ा। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें जब सामाजिक न्याय की लड़ाई का अगुआ बता कर ट्वीट किया, तो समर्थक और विरोधी इसकी विशद व्याख्या करने में जुट गए। रही-सही कसर लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देकर पूरी कर दी।

74वां जन्मदिन बना यादगार- सत्ता में आने के साथ सन् 1990 से ही राज्य में लालू प्रसाद का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया जाता रहा है। ढोल-बाजा, हाथी-घोड़ा, वजनी केक और भोज के साथ नाच-गाना उनके जन्मदिन को हर साल यादगार बना देता था। बीते तीन वर्षों में जेल में रहने के कारण पटना में उनके जन्मदिन पर कोई उत्सव नहीं हुआ। इस बार उत्सव की तैयारी थी, मगर कोरोना के प्रोटोकाल ने कुछ खास नहीं होने दिया। फिर भी राजनीतिक गतिविधियों ने उनके 74वें जन्मदिन को यादगार बना दिया।

सबसे अधिक चर्चित उपेंद्र कुशवाहा का बधाई संदेश- विरोधी दलों में सबसे अधिक चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बधाई संदेश पर हुई। कुशवाहा ने लालू के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में केक काटने की तस्वीर के साथ ट्वीट किया - बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लडने् वाले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसादजी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू को जन्मदिन पर बधाई दी। कुशवाहा के ट्वीट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इन दिनों वे सरकार की सहयोगी भाजपा पर तीखी टिप्पणी करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में लालू के प्रति उनका सौहार्दपूर्ण संबोधन एनडीए के साथ विरोधी दलों को भी हैरत में डाल रहा है।

मुख्यमंत्री ने ऐसे दी लालू यादव को बधाई- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को उनके जन्मदिन पर शुक्रवार को बधाई दी। मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर से लौटने के क्रम में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को लालू प्रसाद के जन्मदिन की याद दिलाई, तो उन्होंने कहा कि हम तो बधाई देते ही रहते हैं। उन्हें जन्मदिन की बधाई!

पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप की मुलाकात लालू प्रसाद के जन्मदिन के बहाने हुई। मांझी ने कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद को टेलीफोन पर जन्मदिन की बधाई दी। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का दावा है कि दोनों नेताओं के बीच देर तक बातचीत हुई।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने चित्रदुर्ग और हुबली में आईसीयू और क्रिटिकल केयर सुविधाओं के साथ 100 बिस्तरों वाले कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया।

DMK यूथ विंग के सचिव और विधायक उदयनिधि स्टालिन ने कोयंबटूर के वालपराई सरकारी अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के राजभवन में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए।

एक नजर

कोविशील्ड की डोज के बीच अंतराल में बदलाव को लेकर हड़बड़ी की नहीं है आवश्यकता

नई दिल्ली । सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविशील्ड टीके की दो डोज के बीच अंतराल में तत्काल बदलाव के मामले में हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। समयावधि में बदलाव के लिए भारत के संदर्भ में उचित वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत होगी। कोविशील्ड की दो डोज के बीच अंतर को थोड़ा कम करने की वकालत करने वाले कुछ अध्ययनों की खबरों के संदर्भ में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा. वीके पाल ने कहा कि इस तरह की चिंताओं पर संतुलित रुख की जरूरत है। कोरोना पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे पाल ने कहा, डोज के बीच अंतराल तत्काल बदलने की जरूरत की बात करने में हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के फैसले बहुत सावधानी से लिए जाने चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब हमने अंतराल बढ़ाया तो हमें उन लोगों को वायरस से होने वाले जोखिम पर विचार करना पड़ा जिन्होंने केवल एक डोज ली थी। लेकिन उसका भी जवाब था कि कई और लोगों को पहली डोज मिल जाएगी और इस तरह अधिक लोगों की एक सीमा तक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पर तकनीकी परामर्श देने वाले समूह में ऐसे लोग भी हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एवं अन्य समितियों में रहे हैं और जिनकी प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर है। इसलिए उनके फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए।

ओडिशा में 5 मई से 11 जून के बीच लॉकडाउन में हुई 1122 संक्रमितों की मौत, 1 जून से बढ़ी मृत्यु दर

भुवनेश्वर । मई महीने से संक्रमण घातक रूप में था। एक महीने तक दैनिक संक्रमण के मामले 10 हजार से अधिक सामने आए। संक्रमण बढ़ने से स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पिछले महीने की 5 तारीख से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। पहले चरण के तालाबंदी में संक्रमण के नियंत्रण में ना आने से पुन~ तालाबंदी अवधी को सरकार ने बढ़ा दिया। इसके बाद 1 जून से संक्रमण की रफ्तार में कमी आनी शुरू हुई, मगर मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आयी। तीसरे चरण की तालाबंदी को खत्म होने में महज पांच दिन बाकी हैं। इस बीच 5 मई से 11 जून के बीच 1122 लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है। एक मई से संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही मृतकों की संख्या में भी इजाफा होने लगा। हालांकि 1 जून से संक्रमण की रफ्तार में कमी आनी शुरू जरूर हुई मगर मृतकों की संख्या में कमी नहीं आ पायी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि मृत्यु दर अगले कुछ और दिनों इसी तरह से रह सकती है।

खबर के मुताबिक कोरोना से अब तक राज्य में 3210 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु दर के मामले में खुर्दा जिला सबसे ऊपर है, जहां अब तक 522 लोगों की मौत हो चुकी है। सुन्दरगड़ जिले में 303, गंजाम जिले में 296, कटक जिले में 201, पुरी जिले में 167, अनुगुल जिले में 148, कालाहांडी जिले में 146, रायगड़ा जिले में 126, बालेश्वर जिले में 113 तथा मयूरभंज जिले में 107 लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे कम 28 लोगों की मृत्यु देवगड़ जिले में हुई है। भद्रक जिले में 34, मालकानगिरी में 34 एवं जाजपुर जिले में 35, सोनपुर जिले में 35 लोगों की कोरोना से जान गई है। राज्य में प्रत्येक दिन संक्रमण की दर .05 से 1 प्रतिशत तक कम हो रही है। इस रफ्तार से यदि संक्रमण कम होता है तो फिर निश्चित रूप से जब तालाबंदी में ढिलाई दिया जाएगा तब संक्रमण नियंत्रण में होगा।

संक्रमण नियंत्रण में आने के बावजूद सम्पूर्ण तालाबंदी खत्म नहीं की जाएगी। कमेटी बैठकर तालाबंदी खोलने के संबंध में निर्णय लेने की बात स्वास्थ्य निदेशक डा. विजय महापात्र ने कही है। उन्होंने कहा है कि पहले संक्रमण की दर 23 प्रतिशत से अधिक थी। हालांकि 10 जून तक संक्रमण दर घटकर 7.9 प्रतिशत तक आ गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. निरोज मिश्र ने कहा है कि राज्य में संक्रमण लगभग 9 प्रतिशत कम हुआ है। संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से कम होने के बाद ही तालाबंदी में ढिलाई दी जानी चाहिए। 17 जून तक लगभग राज्य में संक्रमण दर 5 प्रतिशत या फिर इससे नीचे आने की उम्मीद है। भुवनेश्वर एवं कटक में संक्रमण दर कम नहीं रही है, ऐसे में यहां और कुछ दिनों तक प्रतिबंध जारी रह सकता है। यदि लोग कोविड गाइडलाइन एवं सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंध का अनुपालन करेंगे तो फिर निश्चित रूप से संक्रमण घट जाएगा। उन्होंने कहा है कि तालाबंदी में ढिलाई दिए जाने के बाद अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। जिन लोगों की मृत्यु हो रही है वे दो सप्ताह पहले से संक्रमित होकर इलाज करा रहे थे। संक्रमण कम होने पर आगे चलकर मृत्यु दर भी कम होगी।

मुंबई में जलमग्न हुई सड़कें, दो दिन भारी बारिश का अलर्ट; बीएमसी ने कहा हम हैं तैयार

मुंबई । मुंबई में मानसूनी बारिश का आगमन हो चुका है। पहली ही बारिश ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। लगातार जारी बारिश से मुंबई के सायन ईस्ट इलाके में सड़कें जलमग्न हो गई है, वहीं अंधेरी सब वे भी पानी से लबालब हो चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई के पूर्वी उपनगरों में 89.30 मिमी बारिश हुई, पूर्वी उपनगरों में 92.38 मिमी बारिश हुई, और मुंबई शहर में 79.66 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान मुंबई और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, कुछ स्थानों पर बहुत भारी हो सकती है। हालांकि बीएमसी का कहना है कि मानसून से निपटने के लिए हमने व्यापक तैयारियों कर रखी हैं लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। दमकल विभाग समेत सभी आपदा प्रबंधन इकाइयों को अलर्ट कर दिया गया है।

बीएमसी ने की खाास तैयाारी– बीएमसी ने कहा मुंबई में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए यहां के तटीय और निचले इलाकों के लिए हाइ अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएमसी के विभागों जैसे बस सर्विस बेस्ट, शिक्षा विभाग और स्वास्थय विभाग को स्टैंड बाय में रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति में लोगों के ठहरने के लिए शिक्षा विभाग को आपातकालीन आश्रय की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। मीठी नदी के करीब स्थित रिहायशी इलाकों और क्रांति नगर आदि इलाकों चिह्नित किया गया है, अगर स्थिति बिगड़ती है तो यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।

पूरी रात रुक-रुक कर होती रही बारिश –मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी मुंबई के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया था। जिसमें मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, कल्याण, ठाणे में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी। बता दें कि मुंबई में पूरी रात रुक-रुक कर बारिश होती रही। हालांकि सुबह 7 बजे के करीब बारिश की गति कुछ धीमी थी लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण अंधेरी सबवे, किंग सर्किल, सायन, माहिम और कुर्ला जैसे निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए थे।

बच्चों में कोरोना संक्रमण के बचाव और इलाज के दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली । कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के बीच बच्चों में कोरोना संक्रमण के बचाव और इलाज के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर का प्रयोग न किया जाए। स्टेरायड के इस्तेमाल से भी बचने को कहा गया है। बिना लक्षण के कोरोना संक्रमित से लेकर आइसोलेशन वार्ड और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीकू) में भर्ती गंभीर मरीजों के इलाज के तरीके पर भी बात की गई है।

छोटे बच्चों के मास्क छूने से बढ़ता संक्रमण का खतरा– पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क न पहनने की सलाह दी गई है और इसका कारण यह है कि छोटे बच्चे मास्क को बार-बार छूते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को संक्रमण से दूर रखने के लिए माता-पिता को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के अध्यक्ष व बाल रोग विशेषज्ञ डा. अरुण गुप्ता ने कहा कि माता-पिता घर में भी बच्चों के पास बगैर मास्क के न जाएं। हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही बच्चे को गोद में उठाएं। बच्चे को घर से बाहर न निकलने दें। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग के विशेषज्ञ डा. राहुल नागपाल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का भी दिशा निर्देश यही है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए। हालांकि, इंडियन एकेडमी आफ पीडियाट्रिक्स का मानना है कि दो साल से अधिक उम्र के बच्चों को माता-पिता अपनी देखरेख में मास्क पहना सकते हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर के प्रभाव और उपयुक्त सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई प्रामाणिक डाटा नहीं है। स्टेरायड भी बिना लक्षण और हल्के संक्रमण वाले मरीजों के लिए नुकसानदायक है। इसका प्रयोग केवल अस्पताल में भर्ती गंभीर संक्रमण वाले मरीजों में सख्त निगरानी में किया जाना चाहिए। डीजीएचएस ने कहा है कि इसकी सही खुराक दी जानी चाहिए व खुद से स्टेरायड के इस्तेमाल से बचना चाहिए।

बच्चों के इलाज में डाक्टर रहें बेहद संजीदा– दिशा निर्देश में कहा गया है कि बच्चों के इलाज में डाक्टर बेहद संजीदा रहें। फेफड़े में संक्रमण की स्थिति जानने को बहुत जरूरी होने पर ही सीटी स्कैन कराएं। जो दवाएं चलाएं, उनसे बीमारी की गंभीरता और शरीर को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसकी भी निगरानी करते रहें।

बच्चों को बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता का तोहफा कुदरत से मिला है। 12 साल की उम्र तक बच्चों के गले में पाई जाने वाली थाइमस ग्रंथि (इम्यूनिटी का पावर हाउस) संक्रमण से उनकी बेहतर रक्षा कर सकती है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग के प्रोफेसर डा. विकास मिश्र बताते हैं कि थाइमस ग्रंथि की वजह से बच्चों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। हालांकि, गंभीर या अति गंभीर बीमार बच्चों में सावधानी रखनी चाहिए।

कोरोना की दूसरी लहर में 719 डॉक्टरों की मौत, बिहार और दिल्ली में सबसे ज्यादा गई जान

नई दिल्ली । देश भर में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। यही कारण है कि डॉक्टर हर दिन कोविड संक्रमित मरीजों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर में अबकत 719 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसान इसमें से सबसे ज्यादा बिहार में 111 डॉक्टरों और दिल्ली में 109 डॉक्टरों की मौत हुई है, जबकि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में 79 और पश्चिम बंगाल में 63 डॉक्टरों की जान गई है।

आइएमए के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 1,467 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। महामारी की पहली लहर के दौरान 748 डॉक्टरों की जान चली गई थी। आइएमए के अनुसार, कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक 30 से 55 वर्ष के बीच के डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न के रूप में काम करने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं। इन डॉक्टरों के अलावा, कई गर्भवती महिला डॉक्टरों ने भी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है।

देश भर में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अब कम होती दिख रही है। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 84,332 नए मामले मिले हैं। इसको मिलाकर देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,93,59,155 हो गई है। इस दौरान हुई 4,002 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,67,081 पहुंच गई है। एक दिन में 1,21,311 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 है।

देश में अब तक टीके की 24.93 करोड़ से अधिक डोज दी गई– केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 24.93 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान के 147वें दिन (11 जून) को टीक की कुल 31,50,368 डोज दी गईं। इनमें से 28,48,435 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली और 3,01,933 को दूसरी डोज दी गईं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की चेतावनी- घातक होगी फिर लापरवाही, अनलॉक में लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन ने लोगों को फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि फिर से लापरवाही लोगों के लिए घातक हो सकती है। अनलॉक में अधिस सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले उचतम स्तर पर जाने के बाद कम हो गए हैं। इससे राहत जरूर मिली है, लेकिन यह संक्रमण रुकने की गारंटी नहीं है। इसलिए अनलाक में भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनलॉक का मतलब यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोरोना समाप्त हो गया है। बल्कि, अनलॉक के बाद और यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर पर ठीक तरीके से मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है।

डा. हर्षवर्धन ने टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसे अधिक व्यापक बनाना होगा। केंद्र सरकार देश के सभी वयस्कों के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है ताकि कोई भी व्यक्ति टीके के बिना नहीं रहे। दिल्ली के हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब यहां हालात बेकाबू हुए थे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सहित अन्य कई मंत्रालय व विभागों ने जुटकर हालात को काबू किया था।

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर हो रहा तेजी से काम– डा. हर्षवर्धन ने बताया कि 2014 में पदभार संभालने के बाद से ही पीएम मोदी ने देश के सामने डिजिटल इंडिया का विजन पेश किया था। इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर तेजी से काम हो रहा है।

कोरोना से मौत के आंकड़ों की सही तरीक से नियमित रिपोर्टिंग– केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह नियमित रूप से कोरोना के जिलेवार मामलों और मौत के आंकड़ों की निगरानी के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। मंत्रालय ने बिहार द्वारा कोरोना से हुई मौतों के मामलों में संशोधन किए जाने के दो दिन बाद यह बात कही। बिहार सरकार ने 3,951 लोगों की मौत को आंकड़ों में शामिल किया है, जिनकी जानकारी नहीं मिली थी।बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में अचानक वृद्धि देखी गई थी। राय के स्वास्थ्य विभाग ने महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बुधवार को 9,429 बताई थी।

असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की

नागपुर । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से यहां संघ मुख्यालय में मुलाकात की। एक महीने पहले असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद सरमा का आरएसएस मुख्यालय का यह पहला दौरा है। समाचार एजेंसी पीटीआइ ने संघ के सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरमा ने आरएसएस मुख्यालय में एक घंटे से अधिक समय बिताया। सरमा भागवत से मिले। हालांकि बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं साझा की गई है।

उल्लेखनीय है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बृहस्पतिवार को गरीबी कम करने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन की नीति अपनाने की गुजारिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समुदाय में गरीबी कम करने में मदद के लिए सभी पक्षकारों को आगे आना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन?होंने आगे कहा कि गरीबी की वजह जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि है। सरकार सभी गरीब लोगों की संरक्षक है। सरकार को जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सहयोग की दरकार है।

सरमा ने कहा कि राज?य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को शिक्षित करने का काम करेगी ताकि इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। सरकार मंदिर, सत्रों और वन भूमि का अतिक्रमण नहीं करने दे सकती है।

मुख्यमंत्री ने समुदाय के नेताओं से आत्मावलोकन करने और लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया। अब इस बयान को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्षी कांग्रेस और एआईयूडीएफ एवं अल्पसंख्यक छात्र निकाय ने हिमंत बिस्व सरमा की टिप्पणी को शुक्रवार को दुर्भाग्यपूर्ण, तुच्छ और भ्रामक करार दिया।

गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण पर जल्द होगा फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण पर जल्द फैसला लिया जाएगा।इस संबंध में एक महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाना चाहती है। याचिका में मांग की गई थी कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए।केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआइ) ने 28 मई को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत जारी सिफारिशों में कहा गया है कि एक गर्भवती महिला को निकटतम टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध कोरोना वैक्सीन लगाई ला सकती है। यह भी बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन गर्भावस्था के दौरान कभी भी दी जा सकती है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं कोरोना का टीका लेने के योग्य हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।

सख्ती के बाद ट्विटर को भारत में दिखने लगा बड़ा बाजार, नियमों के मुताबिक रणनीति बनाने के लिए रखेगा स्टाफ डिजाइनर

नई दिल्ली । सरकार की सख्ती के बाद आइटी नियमों को मानने की दुहाई देने वाले माइक्रोब्लागिंग प्लेटफार्म ट्विटर को भारत में अब बड़ा बाजार नजर आने लगा है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कामकाज में बदलाव के लिए उसने स्टाफ डिजाइनर के नाम से एक पद बनाया है। इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को ट्विटर की वैश्विक रणनीति को स्थानीय नियमों के मुताबिक ढालकर उसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी।

सरकार के नवीनतम डाटा के मुताबिक भारत में ट्विटर के 1.75 करोड़ से यादा उपयोगकर्ता हैं। वह भारत के नियमों को मानने से इन्कार कर रहा था। सरकार ने जब सख्ती दिखाती तो वह नियमों को मानने को तैयार हुआ, लेकिन कोरोना महामारी की आड़ लेकर वक्त भी ले लिया है। उसकी वेबसाइट पर करियर खंड में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी, और रेजिडेंट ग्रीवांस आफिसर के साथ ही स्टाफ डिजाइनर-ग्लोबल पार्टिसिपेशन, इंडिया पद के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं।

ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी ने ट्वीट कर इस पोस्ट के बारे में जानकारी दी है। इस पोस्ट पर काम करने वाला अधिकारी भारत के नियमों के मुताबिक कंपनी की रणनीति बनाएगा और स्थानीय टीम की मदद से उसे लागू भी करेगा। माइक्रोब्लागिंग साइट ने कहा कि भारत ट्विटर के लिए एक प्रमुख बाजारों में से एक है और यह उन पहले देशों में से एक होगा जहां एक विशेष क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक रणनीति तैयार करने के लिए कंपनी टीम बनाने का प्रयोग करेगी।

इस हफ्ते की शुरुआत में, ट्विटर ने भारत सरकार को बताया कि नए आइटी नियमों के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति अंतिम चरण में है। वह एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करेगा। सरकार के अंतिम नोटिस के जवाब में, ट्विटर ने कहा था कि वह नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा है।

26 जून को देशभर के राजभवन पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली । देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच, एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर किसान 26 जून को देशभर के राजभवन पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के घर(राजभवन) के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान 26 जून को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और इस दिन को खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे।

किसान 26 जून को आंदोलन के सात महीने पूरे होने पर राजभवन पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। इसके लिए किसी तरह की अनुमति भी किसान नहीं लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 26 जून को अपने प्रदर्शन के दौरान काले झंडे भी दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों से संबंधित मेमोरेन्डम भी सौपेंगे।

26 जून को लेकर किसानों की तैयारी– 26 जून को खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के राजभवन पर प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम राजभवन के पास काला झंडा दिखा कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना मेमोरेन्डम राष्ट्रपति को देंगे।

क्यों चुनी गई 26 जून की तारीख

26 जून वो दिन है जब साल 1975 में इस दिन देश में आपातकाल लागू किया था। इस दिन हमारे प्रदर्शन को सात महीने भी हो जाएंगे। किसानों का कहना है कि किसानों के अलावा इस डिक्टेटरशिप की वजह से नागरिकों की प्रजातांत्रिक अधिकारों पर भी हमला किया जा रहा है। यह एक अघोषित इमरजेंसी है। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान छह महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। कई लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर डेरा डाला है। पिछले साल केंद्र और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध बना हुआ है। किसान 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सरकार कृषि कानूनों के अलावा अन्य मुद्दों पर आंदोलन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के हित में बात की है और वह किसानों से बात करने को तैयार है। अगर किसान संगठन कृषि बिल के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो सरकार उनसे बात करने को तैयार है।

परिणीति चोपड़ा की बिकिनी फोटो को देख प्रियंका चोपड़ा को हुई जलन, कमेंट में लिखी ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों तुर्की में छुट्टियां मना रही हैं. और वहां से लगातार फैन्स के साथ अपनी हॉट फोटोज शेयर कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने खुद की समुंदर किनारे बैठी एक बिकिनी फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. उनको इस अवतार में देखकर उनकी बहन प्रियंका चोपड़ा को काफी जलन महसूस हो रही है. और उन्होंने परिणीति की फोटो पर एक दिलचस्प कमेंट भी किया है.

परिणीति ने शेयर की बिकिनी फोटो

दरअसल परिणीति ने खुद को पहले से काफी फिट कर लिया है. उनके फैन्स उनका नया लुक देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं. फैन्स के लिए परिणीति ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक ब्लैक बिकिनी वाली बेहद ही हॉट फोटो शेयर की है.

फोटो में समुंदर किनारे बैठी काफी ज्यादा सुंदर लग रही है.फोटो को शेयर करते हुए परिणीति ने लिखा, इस फोटो से पहले मैं प्रणायम कर रही थी. ओके ये झूठ है. जहां फैन्स परिणीति की इस फोटो पर प्यार लुटा रहे थे, वहीं प्रियंका ने इस फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि, मुझे बहुत जलन हो रही है. उन्होंने कमेंट में हार्ट वाली इमोजी भी बनाई. परिणीति की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

आखिरी बार इस फिल्म में नजर आई थी परिणीति

वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा आखिरी बार फिल्म साइना में नजर आई थीं. जोकि बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की लाइफ पर आधारित थी. वहीं प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वो इन दिनों लॉस एंजेलिस में अपने पति निक जोनस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं.

दीपिका पादुकोण को पहली बार देखते ही क्या सोच बैठे थे रणबीर कपूर, खुद किया था खुलासा

रणबीर कपूर(Ranbir Kapoor) और दीपिका पादुकोण(Deepika Padukone) कभी लव पार्टनर्स थे, ये बात तो सब जानते हैं.दोनों ने एक-दूसरे के साथ तकरीबन दो साल तक रिलेशनशिप निभाया और फिर इनका ब्रेकअप हो गया. एक इंटरव्यू में रणबीर ने इस बात का जिक्र किया था कि जब उन्होंने पहली बार दीपिका को देखा था तो उनके मन में क्या ख्याल आया था?

रणबीर ने कहा था, मैंने उन्हें तब देखा था जब वह ओम शांति ओम की शूटिंग कर रही थीं. मैं भी उसी स्टूडियो में अपनी डेब्यू फिल्म सांवरिया की शूटिंग कर रहा था. जब मैं अपने स्टूडियो से बाहर निकला तो दीपिका अपना कॉस्टयूम पहनकर मेरे पास से गुजर रही थीं, उस वक्त उन्हें पहली बार देखते ही मैं समझ गया था कि वह बहुत बड़ी स्टार बनेंगी. वह बेहद खूबसूरत दिख रही थीं और अपनी पहली इमेज के बाद वह हमेशा और बेहतर होती ही दिखाई दी हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका को उस दिन फिल्मिस्तान स्टूडियो में देखने के बाद रणबीर ने 24 घंटे के भीतर ही उनका फोन नंबर खोज लिया था और उन्हें कॉल भी कर लिया था. इसके बाद दोनों ने अपने करियर की दूसरी फिल्म %बचना ए हसीनों% में साथ काम किया और फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान और ज्यादा करीब आ गए. फिल्म की इटली में हुई आउटडोर शूटिंग के दौरान रणबीर-दीपिका ने तकरीबन दो महीने का वक्त साथ गुजारा था.

लौटने के बाद एक इंटरव्यू में दीपिका ने ये तक कह डाला था कि वह शादी के बाद इटली में हनीमून मनाना पसंद करेंगी. वैसे आपको बता दें कि दोनों की प्रेम कहानी काफी बुरे मोड़ पर जाकर खत्म हुई थी. दीपिका ने रणबीर को धोखा देते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया था जिसके बाद उन्होंने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद रणबीर कैटरीना कैफ को डेट करने लग गए थे.

जब अनुष्का शर्मा से ब्रेकअप के बाद बोले थे रणवीर सिंह, 'मैं उन्हें बेहद मिस करता हूं'

बॉलीवुड में कई लव स्टोरीज अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाईं लेकिन इनके किस्से काफी मशहूर हुए. एक ऐसी ही जोड़ी अनुष्का शर्मा(Anushka Sharma) और रणवीर सिंह(Ranveer Singh) की है. दोनों ने सबसे पहले फिल्म बैंड बाजा बारात में साथ काम किया था. यह रणवीर की पहली फिल्म थी जबकि अनुष्का की यह दूसरी फिल्म थी. फिल्म में दोनों के काम की काफी तारीफ हुई थी और साथ ही फिल्म भी हिट हुई थी. साथ काम करते हुए इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ-साथ इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी खूब बेहतरीन हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को डेट करने लग गए.

दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री फिल्म %लेडीज वर्सेज रिक्की बहल% में भी देखने को मिली.कुछ समय तक दोनों के बीच सबकुछ ठीक चला लेकिन फिर 2011 में हुए एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान दोनों के बीच बात बिगड़ गई. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक एक्ट परफॉर्म किया जिससे अनुष्का उनसे नाराज़ हो गईं. दोनों सबके सामने ही झगड़ पड़े और पूरे फंक्शन में एक-दूसरे से बात नहीं की. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों का रिश्ता जलन के चलते भी बर्बाद हुआ. एक तरफ अनुष्का जहां उस समय बिग बैनर की फ़िल्में पा रही थीं जबकि रणवीर इंडस्ट्री में जगह ही बना रहे थे. इन्हीं सब बातों के चलते दोनों का रिश्ता आखिरकार टूट गया.एक इंटरव्यू में अनुष्का से ब्रेकअप पर रणवीर ने कहा था, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं. वह प्यार से सराबोर हैं और लोग उन्हें गलत समझते हैं. वह बहुत ही प्यारी और ईमानदार इंसान हैं जिनसे मैं मिला हूं. मैं जब भी उनके खिलाफ कोई निगेटिव आर्टिकल पढ़ता हूं तो आग बबूला हो जाता हूं जबकि अपने ऊपर लिखे निगेटिव आर्टिकल्स पर मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है. आपको बता दें कि रणवीर से ब्रेकअप के बाद अनुष्का की शादी विराट कोहली से हुई जबकि रणवीर ने दीपिका पादुकोण से शादी की.

जब ब्रेकअप के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा से पहली बार मिली थीं आलिया भट्ट, जानिए कैसी थी मुलाकात?

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर फिल्म से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उन्होंने वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया था. फिल्म रिलीज की बाद उनकी नजदीकियां सिद्धार्थ मल्होत्रा से बढ़ गई थीं और दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे. एक इंटरव्यू में आलिया ने खुद सिद्धार्थ को डेटिंग करने की बात कबूली थी और कहा था, मैं उन्हें प्यार करती हूं और कोई स्ट्रेस नहीं है. मैं उन्हें फिल्मों और रियल लाइफ में अपनी उंगली पर नहीं नचाने वाली हूं. हालांकि, सिड-आलिया के बीच कुछ साल सब ठीक चला लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया.

ब्रेकअप के बाद भी सिड-आलिया का मिलना एक बार हुआ था और आलिया ने इस बारे में कहा था, हम बिलकुल नॉर्मल तरीके से मिले थे और हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं थी. हमने इंडस्ट्री में साथ में कदम रखा था और मैं उन्हें बहुत लंबे समय से जानती हूं. हमारे पीछे काफी बड़ी हिस्ट्री है. हमारे बीच कोई गिला-शिकवा नहीं है.

मेरे दिल में उनके लिए केवल पॉजिटिविटी है,उम्मीद करती हूं कि वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे. हमने साथ में ज़िंदगी के कई पड़ाव हासिल किए हैं .जब हम मिले तो हमने खूब बातें कीं और सब ठीक था.कोई निगेटिविटी नहीं थी.

इस मुलाकात के दौरान आलिया के ब्वॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी मौजूद थे.दरअसल, ये सभी एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए थे. आपको बता दें कि सिद्धार्थ से ब्रेकअप के बाद आलिया रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में हैं. वहीं सिद्धार्थ का नाम कियारा आडवाणी के साथ जुड़ रहा है. दोनों इस साल की शुरुआत में वेकेशन मनाने मालदीव भी गए थे.

पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस के सेमीफाइनल मैच के बाद जीत की खुशी जाहिर करते ग्रीस के स्टेपॉन्स।

कृष्णप्पा गौतम की गेंदबाजी में दिखाई देता हैं अश्विन का प्रभाव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृष्णप्पा गौतम को क्रिकेट के उनके शुरूआती दिनों में टीम के साथी खिलाड़ी भज्जी (हरभजन का उपनाम) के नाम से बुलाते थे, लेकिन हरफनमौला खिलाड़ी ने अपने तरीके से जिस तरह से कैरम बॉल को इजाद किया,इसमें उनकी गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन का प्रभाव ज्यादा दिखाता है। गौतम उन छह खिलाड़ियों में से एक है,जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरे के लिए चुना गया है।इस दौरे पर 13 से 25 जुलाई के बीच भारतीय टीम को तीन एकदिवसीय और इतने ही टी20 मैचों की श्रृंखला खेलनी है। गौतम से जब टीम में चयन के बारे में पूछा गया,तब उन्होंने कहा,आप वर्षों से जो सपना देखते है, जब वह सच होता है, तब आप सबसे ज्यादा खुश होते है। घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले गौतम इस साल इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में सुर्खियों में आए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने 32 साल के खिलाड़ी के लिए बड़ी बोली लगायी थी।

गौतम ने कहा,अपने करियर की शुरूआत में मैं भज्जी (हरभजन सिंह) की नकल करता था और मेरे साथी मुझे भज्जी कहते थे। भज्जी की तरह दूसरा गेंद डालने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,नहीं, मैं दूसरा नहीं फेंकता लेकिन कैरम गेंद फेंकता हूं।प्रथम श्रेणी में 166, लिस्ट ए में 70 और टी20 में 42 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी से जब पूछ गया कि क्या उन्होंने अश्विन को देखकर कैरम बॉल करना सीखा है,तब उन्होंने कहा, मैंने इस अपने दम पर विकसित किया है। यदि आपको शीर्ष स्तर पर खेलना है, तो आपको अपने दम पर कौशल विकसित करने की जरूरत होती है। अपने जूनियर दिनों में, मुझे ईरापल्ली प्रसन्ना सर ने भी कोचिंग दी है। उन्होंने कहा, जाहिर है, आप अश्विन जैसे दिग्गज को देखते हैं। मुझे अश्विन की मानसिकता और खेल के प्रति दृष्टिकोण पसंद है।

आईपीएल में चेन्नई की टीम ने गौतम के लिए 9.25 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी लेकिन टीम में मोईन अली की मौजूदगी के कारण उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, आईपीएल में मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। आईपीएल जैसे टूनामेंटों में आपको मैच की ज्यादा चिंता किये बगैर खुद का समर्थन करना होता है। आप मुकाबले में अपनी नीलामी की कीमत के कारण मैदान में नहीं उतरते है। महेन्द्र सिंह धोनी से मिली सलाह पर उन्होंने कहा, माही भाई का सबसे अहम सुझाव यह होता है, कि मौजूदा समय का लुत्फ उठाओ। अपने नैसर्गिक खेल का समर्थन करो और उसी तरह से खेलो जिसे सबसे अच्छे तरीके से जानते हो।गौतम हालांकि राष्ट्रीय टीम से पहले जुड़े रहे हैं। इंग्लैंड के पिछले भारत दौरे पर वह टेस्ट श्रृंख्ला के दौरान नेट गेंदबाज के तौर पर दल में शामिल थे। उन्होंने कहा, देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को गेंदबाजी करना हमेशा अच्छा होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जाहिर तौर पर यह भारतीय टीम के शानदार खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने का अनुभव शानदार था।

गेंदबाजी के अलावा गौतम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में 141 और टी20 में 160 के स्ट्राइकरेट से रन बनाए हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के निदेशक राहुल द्रविड़ भारत की सीमित ओवरों के इस श्रृंखला में टीम के मुख्य कोच के रूप में यात्रा करने की संभावना है। गौतम ने कहा कि उनकी उपस्थिति से निश्चित रूप से उनका काम आसान हो जाएगा।

अनुष्का की कॉफी पर तो खूब हंगामा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जीते तो किसी ने तारीफ नहीं की : प्रसाद

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट में चयनकताओं को टीम के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय प्रायः नहीं मिलता है, लेकिन खिलाड़ियों के चयन या बाहर निकालने की वजह से अक्सर उन्हें लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद को अपने कार्यकाल के दौरान अक्सर इसका सामना करना पड़ा है। एमएसके प्रसाद ने दो साल पहले इंग्लैंड में हुए विश्व कप के दौरान अनुष्का शर्मा से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया, जब चयनकताओं को पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों की आलोचना का शिकार होना पड़ा था।

एमसके प्रसाद 2016 से 2020 तक सीनियर सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017, 2019 विश्व कप और 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए खिलाड़ियों को चुनने में कड़े फैसले लेने पड़े। कई बार इसे लेकर विवाद भी खड़े हुए। लेकिन सिर्फ सेलेक्शन को लेकर ही उनकी आलोचना नहीं हुई, बल्कि 2019 के वनडे विश्व कप में तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर भी सेलेक्टर्स निशाने पर आ गए। तब पूर्व भारतीय विकेटकीपर फारुख इंजीनियर ने एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी के लिए कहा था कि हमारे पास मिकी माउस सेलेक्शन कमेटी है। उन्होंने कहा इसमें शामिल खिलाड़ियों को 12 टेस्ट खेलने का भी अनुभव नहीं है।

इसी घटना का जिक्र करते हुए प्रसाद ने कहा तब तो सेलेक्टर्स को कॉफी सर्व करने के मामले में जबरदस्ती घसीटा गया। खूब हंगामा मचा। लेकिन जब टीम इंडिया ने स्टार खिलाड़ियों की गैरहाजिरी में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हराया, तब किसी ने सेलेक्टर्स की पीठ नहीं थपथपाई। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने हमारे काम को समझा और उसकी तारीफ की। हमारे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। भले ही बाहर वाले कुछ भी बोलें, लेकिन टीम के साथ जुड़े लोगों को पता है कि हमने क्या काम किया है।

उन्होंने आगे कहा हमने युवा खिलाड़ियों को तराशने के लिए जरूरी नया ढांचा खड़ा किया। पहले गेंदबाज अपनी दिमाग और गलतियों से सीखता था, लेकिन अब सारी चीजें तय हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है। गेंदबाजों को बताया जाता है कि उन्हें किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। उनकी गेंदबाजी का कमजोर पहलू क्या है। उन्हें पता है कि बड़े से बड़े बल्लेबाजों को कैसे आउट करना है और इसके लिए फिट रहना भी जरूरी है। प्रसाद के मुताबिक, हम युवा गेंदबाजों की फिटनेस पर शुरू से ही काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे अब नजर आने लगे हैं। पहले गेंदबाज दो टेस्ट के बाद ही चोटिल हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसमें बोर्ड के साथ-साथ सेलेक्शन कमेटी और ट्रेनिंग से जुड़े लोगों का रोल अहम है।

श्रीलंका जाने से पहले मुंबई में 14 से 14 दिन के लिए क्वारंटीन होगी टीम इंडिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। शिखर धवन की अगुआई में टीम इंडिया इस महीने के आखिर में तीन एक दिवसीय और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका दौरे पर जाएगी। श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया को रवाना होने से पहले मुंबई में 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। टीम मुंबई में 14 जून से 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेगी।

खिलाड़ियों को मुंबई के होटल में पहुंचने और बायो बबल में एंट्री करने से पहले कोविड 19 आरटी पीसीआर टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। खिलाड़ी 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे और फिर 28 जून को श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। श्रीलंका पहुंचने के बाद टीम इंडिया को वहां पर भी 3 दिन क्वारंटीन में रहने की जरूरत होगी। श्रीलंका क्रिकेट के जारी दिशा निदेर्शों के अनुसार 3 दिन का आसोलेशन समय पूरा करने के बाद खिलाड़ियों को छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग करने की अनुमति होगी। खिलाड़ी 2 से 4 जुलाई के बीच छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग करेंगे।

रोम ओलंपिक स्टेडियम में इटली और तुर्की के बीच खेले गए सुकर मैच के दौरान गोल करने के बाद खुशी जताते इटली के खिलाड़ी।

राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम में मैच विनर खिलाड़ियों की लाइन लगा दी : वॉर्नर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बीते कुछ सालों में टीम इंडिया पूरी तरह बदल चुकी है। घर में मजबूत टीमों को हराने के साथ ही विदेश में भी टीम जीत दर्ज कर रही है। भारतीय क्रिकेट में आया ये बदलाव रातों-रात नहीं हुआ है। इसके लिए देश में घरेलू क्रिकेट का बिल्कुल नया ढांचा तैयार किया गया। युवा खिलाड़ियों का बड़ा पूल तैयार किया गया। इनके खेल को तराशा गया।इसकारण आज दो टीम इंडिया तैयार हो चुकी है। इसका श्रेय पूर्व भारतीय बल्लेबाज और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ को जाता है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों को तराशने का काम किया, जो आज टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर भी द्रविड़ की काबिलियत के मुरीद हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय क्रिकेट जैसा नजर आ रहा है, उसे बनाने में द्रविड़ का बड़ा योगदान है। उन्होंने मैच विनर खिलाड़ियों की लाइन लगा दी है,इसकारण भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव आया। इस समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को टेस्ट सीरीज में मिली ऐतिहासिक जीत से ही ये बात साबित होती। उस दौरे पर इशांत नहीं खेले थे।विराट कोहली, मोहम्मद शमी एडिलेड में हुए पहले टेस्ट के बाद बाहर हो गए थे। इसके बाद भी टीम ने मेलबर्न टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर की।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और उमेश यादव भी दो टेस्ट नहीं खेल पाए थे। वहीं, रविचंद्नन अश्विन और हनुमा विहारी भी एक-एक टेस्ट नहीं खेले थे। आखिरी टेस्ट शुरू होने के वक्त सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग-11 में शामिल सिर्फ दो खिलाड़ी ही टीम मैनेजमेंट के प्लेइंग-11 में बचे थे। भारत की ओर से पांच खिलाड़ियों ने इस सीरीज में डेब्यू किया था। इसमें मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी और शुभमन गिल। पिछली बार भारत के लिए एक विदेशी दौरे पर इतने डेब्यू 1996 में किए थे। जब इंग्लैंड में 6 खिलाड़ी पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। उसमें से दो राहुल द्रविड़ और पारस म्हाम्ब्रे थे। इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने बीते कुछ साल में भारत के लिए नए खिलाड़ियों की लाइन लगा दी। द्रविड़ जहां नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर रहे, वहीं म्हाम्ब्रे बॉलिंग कोच है।

द्रविड़ और म्हाम्ब्रे ने मिलकर अंडर-16 और अंडर-19 के 150 टैलेंटेड खिलाड़ियों का पूल तैयार किया। इन 150 खिलाड़ियों को 25-25 के अलग-अलग 6 ग्रुप में बांटा गया और फिर हर ग्रुप को जोनल क्रिकेट एकेडमी में एक महीने का कैंप लगाकर ट्रेनिंग दी गई। इसमें से फिर 50 खिलाड़ियों को अलग किया गया और उन्हें नेशनल कैंप में अलग से ट्रेनिंग दी गई। इस एकेडमी में ट्रेनर, फीजियो और कोचिंग स्टाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर के थे।

कई बार नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोच पारस म्हाम्ब्रे, नरेंद्र हिरवानी, अभय शर्मा और राहुल द्रविड़ भी इन कैंप में खिलाड़ियों का हुनर तराशने पहुंच जाते थे। इन जोनल कैंप को चलाने की जिम्मेदारी ट्रेंड कोच के हाथों में थी। इनमें अजय रात्रा, महिला क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच रमेश पोवार जैसे नाम शामिल हैं।

राहुल द्रविड़ ने 2015 में इंडिया अंडर 19 टीम और टीम ए के हेड कोच का पदभार संभाला था। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा रहा कि भारत 2016 में अंडर-19 विश्व कप का उपविजेता रहा और 2018 में वर्ल्ड कप जीता। उनके मार्गदर्शन में ही पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, मयंक अग्रवाल, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जगह बना पाए। इसके अलावा द्रविड़ ने सैमसन को आईपीएल में पांव जमाने में मदद की थी।

फ्रेंच ओपन में जोकोविच ने लाल बजरी के बादशाह को दी मात

पैरिस, (एजेंसी)। राफेल नडाल की मौजूदगी का मतलब था कि फ्रेंच ओपन के शुरू होते ही चैंपियन की इबारत भी लिख दी जाती थी। लेकिन बार ऐसा नहीं हुआ। नडाल को पहली बार सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। राफेल नाडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है और यह नाम उन्हें यूं ही नहीं मिल गया। उनके नाम 13 फ्रेंच ओपन खिताब हैं, जिसका मतलब यह है कि इस कोर्ट पर उन्हें रोक पाना आसान नहीं है। पर शुक्रवार को हुए मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने यह काम कर दिखाया। उन्होंने राफेल नडाल का 14वां फ्रेंच ओपन जीतने का सपना तोड़ दिया।

सेमीफाइनल में नडाल को अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा। क्ले कोर्ट पर 108 मैचों में से यह नडाल की सिर्फ तीसरी हार थी। पहले सेट गंवाने के बाद जोकोविच ने दमदार वापसी की। इस तरह उन्होंने 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 से मैच अपने नाम कर लिया। चार घंटे 11 मिनट तक चले इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों में करारी टक्कर देखने को मिली। हालांकि सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच ने आखिरी के छह गेम्स जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब जोकविच की नजरें अपने दूसरे फ्रेंच ओपन और 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर होंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि नडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचन के बाद खिताब नहीं जीते हों। फाइनल में जोकोविच का सामना पांचवीं वरीयता प्राप्त स्टीफन्स सिसिपास से होगा। यह जोकोविच के करियर का 29वां ग्रैंड स्लैम फाइनल है और सिसिपास का पहला। ग्रीक खिलाड़ी ने जर्मनी ने एलेक्सेजेंडर जेवेरेव को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। अगर रविवार को जोकोविच जीत जाते हैं तो बीते 50 साल में वह पहले खिलाड़ी होंगे जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम दो बार जीते हों।

जोकोविच ने इससे पहले 2016 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। वहीं नडाल को उन्होंने 2015 में फ्रेंच ओपन में हराया था। इसके साथ ही वह फ्रेंच ओपन में नडाल को दो बार हराने वाले इकलौते खिलाड़ी भी बन गए। सिसिपास ने इससे पहले सेमीफाइनल में ज्वेरेव को 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 से हराया था। 35 वर्षीय नडाल ओपन एरा में फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हैं। वह रोजर फेडरर के साथ 20 ग्रैंड स्लैम पर बराबरी पर हैं।

बुखार आने की वजह से पोलैंड ओपन से हटीं पहलवान अंशु मलिक

वारसा, (एजेंसी)। ओलंपिक की तैयारियों में लगी युवा भारतीय पहलवान अंशु मलिक को बुखार आने की वजह से पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता से हटना पड़ा। जब तक उनकी कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उन्हें पृथकवास में रहना होगा। पता चला है कि अंशु शुक्रवार सुबह 57 किग्रा वर्ग में वजन कराने के लिए आई थी। उन्हें बुखार था और इसलिए उनहें प्रतियोगिता से हटने की सलाह दी गई।

भारतीय दल ने बताया कि अंशु प्रतियोगिता से नहीं हटना चाहती थी, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें अलग कर दिया गया। यह पता करने के लिए कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं, उनका नमूना लिया गया है।

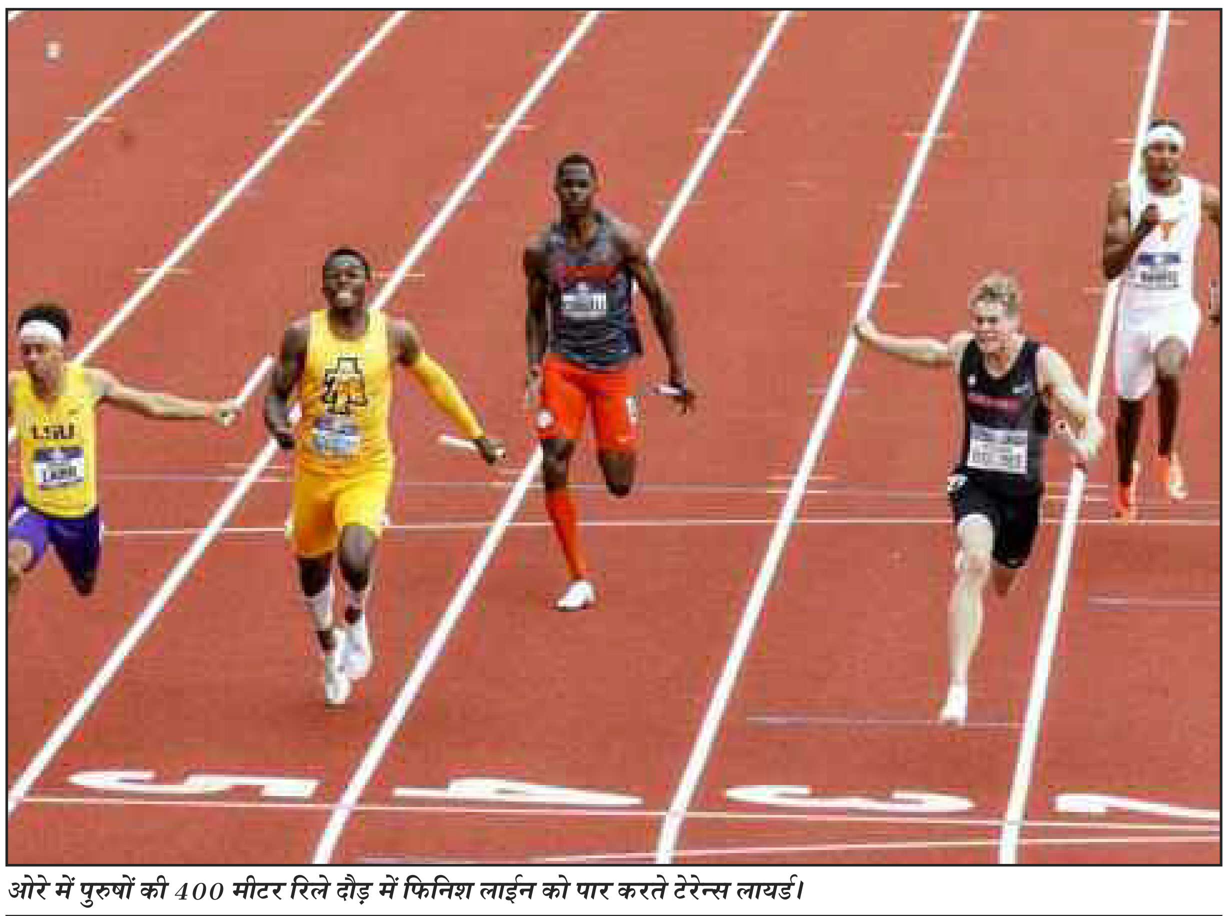

ओरे में पुरुषों की 400 मीटर रिले दौड़ में फिनिश लाईन को पार करते टेरेन्स लायर्ड।

पाक ऑलराउंडर अराफात को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने लंदन गए थे केकेआर के ऑनर शाहरुख खान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर यासिर अराफात ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अराफात ने बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के को-ओनर शाहरुख खान उन्हें तीन साल का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने लंदन गए थे। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 2008 में हुए आईपीएल के पहले सीजन में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 2009 में हुए आईपीएल में वह नहीं खेल पाए थे।

सन 2010 में नीलामी के लिए उपलब्ध होने के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किसी भी फ्रेंचाइजी ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अराफात ने खुलासा किया है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने उनसे करार पर बातचीत के लिए एक शख्स को पहले भेजा था। इसके बाद खुद शाहरुख ने उन्हें फोन किया और फिर बाद तीन साल के अनुबंध की पेशकश के लिए खुद लंदन आए थे। अराफात ने बताया कि मैं 2008 में आईपीएल का पहला सीजन नहीं खेल पाया था और दूसरे संस्करण से पहले कोलकाता टीम ने एक खास स्काउट को मेरे लिए इंग्लैंड भेजा था।

उसने मुझे बताया कि शाहरुख खान काफी करीब से मेरे खेल और आंकड़ों पर नजर रख रहे हैं। अराफात ने कहा मुझे लगता है कि स्काउट मुझसे मजाक रहा है और वह किसी प्रैंक का हिस्सा है। उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया था, लेकिन मैंने पलटकर कभी फोन नहीं लगाया। पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने आगे बताया कि फिर मेरे पास भारत से फोन आया और फोन पर बात करने वाले शख्स ने मुझसे पूछा कि आपने क्यों हमसे संपर्क नहीं साधा।

तब मुझे पता चला कि वह स्काउट झूठ नहीं बोल रहा था। केकेआर मुझसे तीन साल का करार करना चाहती थी। अगले दिन शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और कहा कि बोर्ड पर आपका स्वागत है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी टीम के लिए खेलें। बाद में वो लंदन भी आए। उल्लेखनीय है कि अराफात को कभी आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन वह काउंटी क्रिकेट खेलने के साथ ही बिग बैश लीग का भी हिस्सा रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 3 टेस्ट, 11 वनडे और 3 टी20 खेले। वह टी20 विश्व कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम के सदस्य भी रहे थे। अराफात तो आईपीएल नहीं खेल पाए, लेकिन शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, यूनिस खान, मिस्बाह-उल-हक जैसे कई पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल 2008 का हिस्सा बने थे।

मनिका राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सोनीपत में 20 जून से राष्ट्रीय शिविर में शामिल होंगी। मनिका यहां मिश्रित युगल के अपने जोड़ीदार शरत कमल के साथ अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास सत्र से इस जोड़ी को आगामी ओलंपिक की तैयारियां का अच्छा अवसर मिलेगा। वहीं इससे पहले मनिका और जी साथियान ने इस अभ्यास शिविर में भाग लेने से मना कर दिया था।